● वर्ष-2
● अंक-149
रायपुर, गुरुवार
09 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए यूपीए के 9 साल और मोदी सरकार के 9 साल के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की तुलना की। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि यूपीए के 9 साल की सरकार में एमएसपी 134 प्रतिशत बढ़ा। जबकि मोदी सरकार के 9 साल में यह बढ़ोतरी मात्र 55 फीसदी है। वैसे तो आर्थिक विषयों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में आर्थिक विचारधारा के नाम पर ही राजनीति चल रही है। कई बार ऐसे आर्थिक विषयों पर भी राजनेता अपनी पीठ थपथपाते है जिनसे बड़ी संख्या में गरीबों का कोई भला नहीं होता लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। यह बात सही है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अभी प्रदेश सरकार किसानों के धान को 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है। इसका मतलब है केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य से 600 रुपए अधिक का मूल्य किसानों को मिल रहा है। लेकिन डॉ मनमोहन सिंह सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया क्या उससे किसानों की समस्या समाप्त हो गई? अगर ऐसा होता तो उसी साल में देश के हजारों किसान आत्महत्या क्यों करते? दरअसल हमारे देश में सभी किसानों को एक परिभाषा से आंकलन करते है जबकि देश हो या छत्तीसगढ़ 60 फीसदी किसान ऐसे है जिनका औसत खेत का रकबा एकड़ के करीब है। इस एकड़ के रकबे में फसल उत्पादन करने की अपनी सीमा है। ऐसे में समर्थन मूल्य कितना भी बढ़ा लें छोटे किसानों की गरीबी दूर नहीं होने वाली। न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर अब तक की सरकारों ने जो किया है उससे बड़े किसानों को ही फायदा मिला है। छत्तीसगढ़ में भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9 हजार रुपए प्रति एकड़ सरकार दे रही है उससे 20-30 एकड़ से अधिक के किसानों को तो एक मुश्त फायदा हो रहा है। एक-दो एकड़ वाले किसान को इसमें कुछ मिलता नहीं और जो मिलता है वह फसल का मूल्य बढ़ने के फलस्वरुप कृषि लागत में बढ़ोतरी होती है उसमें बराबर हो जाता है। अर्थशास्त्र का नियम है जब आप एक आवश्यक वस्तु का मूल्य बढ़ाएंगे तो अन्य वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। ऐसा होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ महंगाई के कारण छोटे किसानों को नहीं मिलता। ऐसा ही डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ। समर्थन मूल्य तो बढ़ा लेकिन बीज, खाद, कीटनाशक सहित साबुन, तेल, दाल, शक्कर की कीमत बढ़ने से किसानों के पास कुछ बचा नहीं। राजनीतिक नारा देना अलग बात है और किसानों का कल्याण करना इससे अलग है।

कांग्रेस की बर्बादी पर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में होगा शोध -पीएम

ईडी का करें धन्यवाद, जिसने विपक्ष को एक मंच पर ला दिया

नई दिल्ली। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी समेत संपूर्ण विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मौके को मुसीबत में पलटना यूपीए की आदत थी। मौके के समय से 2 जी में फंसे थे, परमाणु डील के समय कैश फॉर वोट कांड में लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों में हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। एक नेता ने कहा था हार्वर्ड में स्टडी होगी। हार्वर्ड में स्टडी हो चुकी है। इस स्टडी का टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा वक्त भी आएगा जब कांग्रेस की बर्बादी पर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होगा और इसे दुबाने वालों पर भी शोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईडी का धन्यवाद करें, जिसने विपक्ष को एक मंच पर ला दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही थी। ये बहुत फिट बैठता है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं। ये लोग बिना सिर पैर की बातें करते हैं। आत्मचिंतन करके खुद के विरोधाभास को भी ठीक करें। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं। भारत कमजोर हो रहा है। अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों से फैसले

करवा रहा है। पहले ये तो तय करो की भारत कमजोर हुआ या मजबूत हुआ।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में भारत में 90 हजार स्टार्टअप्स आए हैं। हम दुनिया में इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के टियर-टू, टियर थ्री शहरों में पहुंचा है। महामारी के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम का विशाल परिमाण एक स्थिर और निर्णायक सरकार का एक उदाहरण है। हमने %मेड इन इंडिया% वैक्सीन विकसित की और नागरिकों को टीकों की मुफ्त खुराक प्रदान की। भारत आज मैन्यूफैक्चरिंग ।ह्ल्ड्ड के रूप में उभर रहा है। दुनिया भारत की इस समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं।

इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा ईकोसिस्टम,समर्थकज्डछल रहे थे। और खुश होकर कहने लगे,ये हुई न बात! शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया हैज्अच्छे ढंग से कहा गया हैज्ये कह-कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं,वो अब आ रहे है।

पीएम मोदी ने कहा कि सदन में हंसी-मजाक, टीका-टिप्पणी, नोंक-झोंक होती रहती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं। गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों व हमारे पड़ोस में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे समय में कौन हिंदुस्तानी गौरव नहीं करेगा कि उनका देश दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी है। 100 साल में आई हुई यह भयंकर महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बंटा हुआ विश्वज्इस स्थिति में भी, संकट के माहौल में, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास और गौरव से भर रहा है।

मोदी अडानी से जुड़े मसले पर नहीं की कोई बात-राहुल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पीएम के भाषण से संतुष्ट नहीं हूं

लेकिन इससे सच्चाई का पता चलता है। जांच की बात नहीं हुई है। अगर वे दोस्त नहीं हैं तो पीएम को एक बार कहना चाहिए था कि जांच होगी। राहुल गांधी ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण पर राष्ट्रपति को पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने बहुत सच्चाई का खुलासा किया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अडानी विवाद को लेकर सदन में भाषण से पीएम हैरान थे और व्यापारिक समूह के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं करने के लिए सवाल भी उठाए। राहुल ने कहा कि पीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। उनके भाषण से सच्चाई दिखती है। अगर(अडानी) मित्र नहीं है तो उनको(पीएम) कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। शैल कंपनी, बेनामी पैसा घूम रहा है उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।

अदाणी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो- सुब्रमण्यम

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि केंद्र सरकार को गौतम अदाणी की पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और फिर इस संपत्ति की नीलामी की नीलामी कर देनी चाहिए। दरअसल जब स्वामी से अदाणी मामले और इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने को लेकर सवाल किया गया तो स्वामी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अदाणी समूह की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करें और फिर इसकी नीलामी से मिले पैसों को उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अदाणी के शेयरों में आई गिरावट से अपना पैसा गंवाया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अदाणी से डील नहीं हो सकी लेकिन मैं कई कांग्रेस नेताओं को जानता हूं कि जिनकी अदाणी के साथ डील है लेकिन मुझे कांग्रेस की परवाह नहीं है मैं बस चाहता हूं कि भाजपा की पवित्रता साबित होनी चाहिए। आम लोगों की राय है कि मोदी कुछ छिपा रहे हैं और अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सफाई दे। बता दें कि वित्तीय फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में अदाणी समूह पर शेयरों में हेरा-फेरी करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद से अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और जेपीसी से मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है। बीते कई दिनों से इस मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ था। जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुशर्रफ के निधन पर दुख जताया था। जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि मुशर्रफ ने भारतीय सैनिकों की हत्या की थी लेकिन करगिल युद्ध में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने खुद लोगों को गोलियों से नहीं उड़ाया था।

सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि करगिल युद्ध के पीछे नवाज शरीफ का दिमाग था। ऐसे में लोगों को उन पर निशाना साधना चाहिए। स्वामी ने कहा कि मुशर्रफ से वह कई बार मिले थे और मुशर्रफ भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते थे।

राज्यपाल से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के युवा आदिवासी विद्यार्थियों ने मुलाकात की

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में श्री तिलक नाथ पोद्दार के नेतृत्व में उत्तर-पूर्वी भारत के सातो राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश) के आदिवासी समुदायों के युवा विद्यार्थियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी युवाओं को संबोधित करते हुए, उनके छत्तीसगढ़ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन किया।

प्रमुख समाचार

अल्पसंख्यकों के रहने के लिए सबसे मुफीद जगह है भारत, 110 देशों में टॉप पर

कराची। पाकिस्तान भले ही मुसलमानों को लेकर भारत को घेरने की लाख कोशिशें करता हो।

लेकिन भारत में अल्पसंख्यक जितने मजे में रह रहे हैं, उतनी अच्छी हालत में दुनिया के कई देशों में भी नहीं मिलेंगे। ओवैसी जैसे नेता भले ही ये आरोप लगाते हों कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि इस देश में मुसलमान पढ़ें। कांग्रेस की तरफ से देश में धार्मिक और जातिय भेदभाव बढ़ने की बात की जाती हो। लेकिन सच तो ये है कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वो अपनी धर्म और संस्कृति पर आस्था रखें। साथ ही उसके मुताबिक आचरण करें। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस (सीपीए) के मूल्यांकन के अनुसार, धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों में नंबर एक के रूप में स्थान दिया गया है।

शाह-अंबानी जैसे की सुरक्षा करने वाले बलों के लिए मनोवैज्ञानिक क्यों किया जा रहा नियुक्त

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत आने वाला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पास 6,000 से अधिक कर्मियों का एक विशेष वीआईपी सुरक्षा (वीएस) विंग है, जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और गौतम अडानी सहित 110 वीवीआईपी की सुरक्षा करता है। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल अब अपने वीआईपी सुरक्षा इकाई कमांडो के विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मापदंडों का विश्लेषण करने के लिए एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक को नियुक्त करने की मांग कर रहा है। सीआरपीएफ की तरफ से 1 फरवरी को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

स्वामी की सांसद पुत्री संघमित्रा भी कर सकती हैं साइकिल की सवारी

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की सांसद

और विवादित नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की पुत्री संघमित्रा मौर्य का 'पिता प्रेम' उनकी सियासत पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले वर्ष विधान सभा चुनाव के समय बीजेपी की पार्टी लाइन से हटकर सपा नेता और अपने पिता स्वामी प्रसाद मार्या का समर्थन करना और अब स्वामी की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का साथ देना भाजपा आलाकमान को रास नहीं आ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी की विवादित टिप्पणी पर पिता का समर्थन करने वाली संघमित्रा को साफ कह दिया है कि अब उन्हें तय करना होगा कि भविष्य में वह किसके साथ खड़ी होंगी। एक निजी चैनल से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि संघमित्रा बीजेपी की सांसद हैं और 2019 में जनता ने उन्हें सांसद चुना है। हमारी पार्टी का हिस्सा हैं लेकिन अब आगे उन्हें तय करना है कि आगे उनकी लाइन क्या होगी।

फुटपाथ पर ठेले लगाना जनहित के खिलाफ, हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पैदल चलने वाले लोगों को ट्रैफिक में परेशानी ना हो, इसलिए

फुटपाथ बनाए जाते हैं लेकिन अगर उन पर ठेले लगाने की अनुमति दी जाती है तो फिर इससे फुटपाथ बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। जस्टिस एसबी शुक्रे और जस्टिस एमडब्लू चंदवानी की डिविजन बेंच ने यह एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। साथ ही बेंच ने बृहनमुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए। बता दें कि बीएमसी ने बीते साल वर्ली इलाके में स्थित एक अस्पताल के बाहर 11 स्टॉल मालिकों को फुटपाथ पर ठेला लगाने की अनुमति दी थी। बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ द बॉम्बे मदर्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर सोसायटी नामक एनजीओ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में कहा गया है कि बीएमसी ने अस्पताल, शैक्षित संस्थान और पूजा स्थलों के 100 मीटर के दायरे में घूम-घूमकर सामान बेचने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

राज्यपाल के भाषण के बीच भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा में अपने उद्घाटन भाषण में बुधवार को केंद्र सरकार से गरीब लोगों के लिए राज्य को धन जारी करने का आग्रह किया। उनका भाषण ममता बनर्जी सरकार और सत्तारूढ़ टीएमसी के केंद्र पर राज्य को धन जारी न करने के आरोप लगाने के बाद आया है। राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि मनरेगा, ग्रामीण आवास और ग्रामीणों सड़कों के क्षेत्र में राज्य राज्य बेहतर कर सकता था। 2021-22 में पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में नंबर एक रहा है। लेकिन इस वर्ष राज्य को अभी तक धन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि केंद्र गरीब लोगों के हित में जल्द ही धन जारी करेगा और पश्चिम बंगाल जल्द से जल्द मनरेगा, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़कों में नंबर एक स्थान पर बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ा था। अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, राज्यपाल ने सदन में जो कुछ भी कहा है वह सिर्फ एक नियम है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को पढ़ना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के विधानसभा में संबोधन के बीच भाजपा विधायकों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन से बहिर्गमन किया।

उपासना स्थल अधिनियम में मठों मंदिरों के पैसे लेती है सरकार

नीरज कुमार दुबे

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को निरस्त करने और देशभर के मठों-मंदिरों की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की आवाज फिर जोर पकड़ रही है। हम आपको बता दें कि अभी पिछले सप्ताह राज्यसभा में भाजपा सांसद हरनाथ यादव ने निजी तौर पर उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) निरस्त विधेयक, 2022 को पेश करना चाहा था। इसे उच्च सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध भी किया गया था लेकिन अडाणी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसलिए यह विधेयक सदन में पेश नहीं किया जा सका। हालांकि कांग्रेस ने इस विधेयक को पेश किये जाने से रोकने की तैयारी भी कर ली थी क्योंकि कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने आपत्ति जताते हुए राज्यसभा सचिवालय को नोटिस दिया था। अपने नोटिस में उन्होंने कहा था कि उन्हें इस विधेयक पर आपत्ति है क्योंकि यह हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने, साझा जीवन और सदियों पुराने भाईचारे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करता है। यही नहीं, हाल ही में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इबादतगाहों से संबंधित 1991 का कानून खुद हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, जिसे संसद ने पारित किया है इसलिए उसको कायम रखना सरकार का कर्तव्य है। बोर्ड ने 1991 के कानून की याद दिलाते हुए कहा है कि 'उपासना स्थल अधिनियम-1991' को बरकरार रखने के लिए बोर्ड पैरवी कर रहा है। हम आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी और गौरी श्रृंगार विवाद तथा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह जैसे कुछ मामले हाल में सामने आये हैं जिनमें इस अधिनियम का हवाला दिया गया। यह अधिनियम कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के उपासना स्थल को, किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता और यदि कोई इसका

उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार 1991 में लेकर आई थी, यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था।

हम आपको यह भी बता दें कि उपासना स्थल अधिनियम यानि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे असंवैधानिक घोषित करने की गुहार भी लगाई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान मनमाने और असंवैधानिक हैं। याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों को उनके पूजा स्थल पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दावे करने से रोकता है और उन्हें अपने धार्मिक स्थल दोबारा पाने के लिए विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने से रोकता है।

अश्विनी उपाध्याय की ओर से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2, 3 और 4 को विशेष रूप से चुनौती देते हुए उसे असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करते हैं। अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि यह एक्ट संविधान में दिए गए समानता के अधिकार, जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कानून बनाया है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि जिन धार्मिक स्थलों पर आक्रमणकारियों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, उस अतिक्रमण को हटाने और अपने धार्मिक स्थल वापस पाने का कानूनी मार्ग प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से बंद कर दिया गया है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विषय पर लोगों का कोई जाने का अधिकार छीन ले। दूसरी ओर, बात यदि मठों-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की करें तो आपको बता दें कि इसके लिए साधु-संत बड़ा अभियान छेड़ चुके हैं। उत्तराखण्ड में जिस तरह से भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को मान लिया था उससे संतों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनावों से पहले मठों-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। माना यह भी जा रहा है कि संघ परिवार ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का अभियान सफल होने के बाद अब मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है इसलिए इस अभियान से आम जनमानस को जोड़ा जा रहा है। एक ओर जहां संघ परिवार अपने मिशन को अपने तरीके से पूरा करने में लगा हुआ है वहीं दूसरी ओर संत समाज ने भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाते हुए अपना अभियान छेड़ दिया है। संतों का कहना है कि सरकारें केवल मंदिरों का अधिग्रहण करती हैं, मस्जिद या चर्च का नहीं। संतों का यह भी कहना है कि यदि सरकार मंदिर को जनता की संपत्ति समझती है तो पुजारियों को वेतन क्यों नहीं देती? संतों का यह भी कहना है कि यदि मस्जिदें मुस्लिमों की निजी संपत्ति हैं, तो मौलवियों को सरकारी खजाने से वेतन क्यों दिया जाता है? संतगण साल 2014 में आये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दे रहे हैं जिसमें अदालत ने तमिलनाडु के नटराज मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाले आदेश में कहा था कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है सरकारों का नहीं।

फेडरेशन द्वारा वेतन विसंगति को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू

नगरी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय निर्देशानुसार रावणभाठा मैदान नगरी में सोमवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन के प्रथम दिवस छत्तीसगढ़ महतारी एवं भारत माता के पूजा अर्चना,व राजकीय गीत के साथ प्रारंभ किया गया। सोमवार को आंदोलन में वर्तमान भूपेश सरकार के द्वारा पिछले सत्र दिसंबर 2021में 18 दिनों की अनिश्चित किलीन हड़ताल के बाद कमेटी बनाकर हमारे मुख्य मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही वेतन विसंगति को दूर किया गया। सरकार के द्वारा हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ साथियों को प्रधान पाठक बना दिया गया किंतु, उन्हें भी वेतन विसंगति का लाभ नहीं मिला। नवनियुक्त प्रधान पाठक साथी समतुल्य वेतन में आ चुके है।

भूपेश सरकार को सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा हमारी मांगों को अभिलंब पूर्ण करने के लिए बार-बार एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है।किंतु सरकार के द्वारा अभी तक इस हेतु कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।जिससे सहायक शिक्षक फेडरेशन के साथियों में काफी नाराजगी है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश होना

पड़ा।

सहायक शिक्षक फेडरेशन/शिक्षक फेड़रेशन के सचिव गजानंद सोन व गोविंद साहू मिड़िया प्रभारी,ने बताया कि आगामी समय में राज्य सरकार को हमारी मुख्य माँग प्रथम नियुक्ति तिथि वेतन विसंगति दूर करना होगा। क्योंकि इसी सरकार के मंत्री सम्माननीय टी.एस.देव एवं स्वयं मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारे वर्ग 1 एवं 2 के साथियों के वेतन की तुलना में सहायक शिक्षक साथियों के वेतन में भारी असमानता की बात को स्वीकार किया था। जिसे छ.ग.कांग्रेश के द्वारा अपने घोषणापत्र में भी प्रमुखता से स्थान दिया गया थ, किंतु सरकार बनने के 4 साल पूर्ण होने के बाद भी, सहायक शिक्षक फेडरेशन के मुख्य मांग,प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाया गया। आज के आंदोलन को शरीफ बिग मिर्जा अध्यक्ष, प्रकाश चंद साहू उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष चैंपेश्वर साहू, शशिकांत बैरागी अध्यक्ष आन्दोलन समिति, टीकाराम कुंजाम, अनिल कुमार साहू अंकेक्षक, ममता प्रजापति अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, कुमारी साहू, रोशन शांडिल्य, टीका राम कुंजाम, सुरेन्द्र प्रजापति के द्वारा आंदोलन को संबोधित किया गया।

आज के आंदोलन में राज कुमार नेताम, सुनील कुमार सिन्हा, कृष्ण कुमार साहू, योगेश्वरी ध्रुव, नीलिमा साहू, अफ्साना खान, मेनका कश्यप, दूज नेताम लक्ष्मी नेताम, दीक्षा देव, किरण, मनोज देवांगन, माधवी, किरण लता शांडिल्य, उमेश्वरी भंडारी, नरेंद्र कुमार साहू कैलाश पटेल, दीपक फरिकर, धनंजय साहू, कृष्ण कुमार नेताम, यूरेश झारिया, भगवत दयाल, कैलाश पटेल, प्रज्ञा विशेन, अनिता भंडारी, गरिमा सिन्हा, खिलेश्वरी मंडावी, स्नेह लता कुर्रा, आशा सोनी, एवं सभी सकुलों से सहायक शिक्षक, एवं नव नियुक्त प्रधानपाठक साथियों ने आज के आंदोलन में भाग लेकर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक फेडरेशन/समग्र शिक्षक फेडरेशन की मुख्य मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति दूर करने हेतु मांग एवं अपील किया गयाहैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

कसडोल क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों में नियमित समय पर नहीं पहुँच रहे हैं शिक्षक

■ विभाग की उदासीनता और संरक्षण में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ हो रहा है खिलवाड़

कसडोल। शिक्षा विभाग की उदासीनता कहे या संरक्षण विकाशखण्ड कसडोल के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में पदस्थ शिक्षक नियमित समय मे स्कूल नहीं पहुँच रहे है।और बाहुबली शिक्षको की कमी भी नहीं है जो अपने पहुंच और रुतबे के तेवर में शाला जाना तो दूर अपनी उपस्थिति रजिस्टर में डंके की चोट में कर आते हैं।किंतु इन सबसे जानकारी से उच्च अधिकारी हमेशा रटे हुए जुबान में अनभिज्ञता जाहिर करते हैं।इसलिए क्षेत्र में दिनों-दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है जब गुरु ही शिक्षा का अलख जगाने से रुचि नहीं रखते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे?अपने समाज अपने परिवार और देश का कैसे नाम आगे बढ़ाएंगे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आ रहें हैं। शिक्षा

विभाग द्वारा जारी नियमित समय का पालन नहीं कर रहे हैं, शिक्षक जहाँ समय में स्कूलों में पहुंचने के बजाय यत्र-यत्र घूमते नजर आ जाते हैं, जिससे उच्च अधिकारियों के मॉनिटरिंग पर सवालिया निशान लग रहा हैं।

शासकीय नौकरी करने वाले शिक्षक स्वयं अपने बच्चों को मुख्यालय स्थित निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कराने के नाम पर पदस्थ विद्यालयों के समीपस्थ पैतृक गांव होने के बावजूद विकासखंड मुख्यालय में निवासरत हैं और अपने बच्चों को पहले निजी विद्यालय में पहुंचाने के बाद ही अपने पदस्थ विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने 20 -25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। फिर अपने बच्चों को उनके विद्यालयों से घर वापस लाने के लिए अध्यापनरत विद्यालयों से जल्दी आ भी जाते हैं।छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में सुबह 9.45 को प्रार्थना के दौरान समस्त शिक्षकों का विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है ,जबकि विकासखंड मुख्यालय में निवासरत शिक्षक 10 बजे के बाद भी नगर भ्रमण करते नजर आते हैं। विद्यालयीन समय में नगर में दिखे जाने पर उन शिक्षकों के संबंध में पूछे जाने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विद्यालय से सम्बंधित कार्य कराने का हवाला दिया जाता है।इस संबंध में बीईओ राधेलाल जायसवाल से जानकारी हेतु फोन से संपर्क किया तो फोन की घंटी जाता रहा लेकिन फोन रिसीव नहीं किया।

छत्तीसगढ़िया व्यक्ति ही होगा मुख्यमंत्री का चेहरा : संजीव झा

■ 19 को राजधानी में आप का होगा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन

दुर्ग। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली विधायक संजीव झा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 19 जनवरी को राजधानी रायपुर में पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढिया ही मुख्यमंत्री बनेगा।

श्री झा ने कांग्रेस व भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल के भाजपा के कुशासन से परेशान होकर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को सत्तासीन किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कम समय में ही भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ डाले। छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बना लिया है। सीएम के सचिव की कोल मामले में संलिप्तता उजागर हुई है। भ्रष्टाचार के ऐसे कई और भी मामले हैं। जिस पर राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सारी योजनाएं फेल है। योजनाओं की आड़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों, युवा बेरोजगारों, महिलाओं व गरीब वर्ग के साथ छल किया गया है। आप के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति से खेती, युवा बेरोजगारों को रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। विधानसभा चुनाव में आप से सीएम का चेहरा कौन होगा से जुड़े सवाल के जवाब में श्री झा

ने कहा कि छत्तीसगढिया व्यक्ति ही सीएम का चेहरा होगा। चुनाव के पहले पार्टी द्वारा सीएम का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। टिकट वितरण के लिए सर्वे किया जाएगा। जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा।

आम आदमी पार्टी के कार्यो से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए टिकट वितरण में नए व पुराने कार्यकर्ताओं का बंधन नहीं होगा। जीत ही प्रमुख लक्ष्य होगा। श्री झा ने कहा की दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 5 साल में बड़े-बड़े विकास कार्य किए हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त स्वास्थ्य की जांच व दवाई मुक्त दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह सुविधाएं अभी भी कोसों दूर नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है। दोनों पार्टी छल से वोट लेने की राजनीति में लिप्त है। आप के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने बताया कि 19 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के अलावा पार्टी की गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।

मनेंद्रगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भतपुर जिले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट को चार सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। पार्टी की मांग है कि तेंदुए और बाघ के हमले का शिकार हुए लोगों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने डीएफओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें भी हटाने की मांग की है।

वन विभाग के अफसरों की तय हो जवाबदेही

दरअसल, मनेंद्रगढ़ में पिछले एक माह में तेंडुआ तीन लोगों की जान ले चुका है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पिछले हफ्ते बाघ ने भी एक युवक को मार दिया था। इसके बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि ग्रामीणों की जान बचाने में वन विभाग नाकाम रहा है। अफसरों की जवाबदेही तय करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।

चार सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

1. मृतकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। 2. मृतक के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा मिले। 3. घायलों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए। 4. डीएफओ को लापरवाही के चलते हटाया जाए।

क्षेत्र में मुनादी तक नहीं कराई गई

आप के जिलाध्यक्ष रमा शंकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि वन्य जीवों के हमले में शिकार लोगों के लिए वन विभाग जिम्मेदार है। लगातार वन्य प्राणी लोगों को शिकार बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मुनादी तक नहीं कराई गई है और न ही कोई अलर्ट ही जारी किया गया है। इसके चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जान भी संकट में है।

भूपेश सरकार में महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है: अशोक

■ जिला हाथ करघा विभाग दुर्ग ने ग्राम भंसूली (के) कौही व लोहरसी में बुनाई प्रशिक्षण की शुरुआत की

पाटन। छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर संस्कृति एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।उसी कड़ी में जिला प्रशासन दुर्ग के निर्देशानुसार जिला पंचायत दुर्ग ने बुनाई प्रशिक्षण शिविर के लिए जिला हाथ करघा विभाग दुर्ग को जिम्मेदारी सौंपी है।जिसका शुभारंभ अशोक साहू उपाध्यक्ष ज़िप दुर्ग, श्रीमती रामबाई सिन्हा अध्यक्ष जप, देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी उपाध्यक्ष जप, दिनेश साहू सभापति जप, रमन टिकरिहा सभापति जप, मनोरमा टिकरिहा सरपंच, तुलसी डहरिया सरपंच, कमलेश साहू उपसरपंच, डा केके साहू सेक्टर प्रभारी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। पाटन ब्लॉक में जनप्रतिनिधियों एवं महिलाओं की मांग पर बुनाई प्रशिक्षण के लिए भंसूली (के),कौही और लोहरसी का चयन कर लगभग 60 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ज़िप उपाध्यक्ष अशोक साहू ने भूपेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज ग्रामीणों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ स्वालंबन एवम ग्राम स्वराज स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। नरवा,गरुवा, घुरुवा एवम् बाड़ी योजना साकार होते दिख रही है। छत्तीसगढ़ की

परंपरा,संस्कृति, भांचा रामचंद्र जी की स्मृतियों को सहेजने के साथ हमारी माटी प्रेम की भावना का अहसास दिलाने वाली भूपेश सरकार पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। सहायक संचालक राजू कोल्हे ने विभागीय जानकारी प्रेषित करते हुए प्रशिक्षार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महेश साहू, गीता डहरिया, गोमती साहू पूर्व सरपंच, धनी राम देवांगन, धनंजय साहू, जिधन देवांगन, नरेश देवांगन, दिलेश्वरी साहू, सुषमा, सरोज, पूजा साहू, दिगेश्वरी साहू, रजनी साहू, कौशल्या साहू, ऋतु, तुलेश्वरी, मोहिनी, मीना, खिलेश्वरी, गीतेश्वरी निर्मल, मोनिका सेन, रत्ना निर्मल, ललिला, रानी साहू सहित परिक्षार्थी एवम् ग्रामीणजन उपस्थित थे।

हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा घुघवा में

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन द्वारा आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 8 फरवरी की दोपहर 12,30 बजे पाटन ब्लाक के ग्राम बेंद्री से घुघवा में हुआ।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शहर के नजदीक पहुंचा हाथियों का झुंड

कोरबा। कोरबा में लव हरदी बाजार वन परिक्षेत्र में से निकलकर हाथियों का झुंड शहर के नजदीक पहुंच गया। एक दर्जन हाथियों के झुंड में 6 नन्हे शावक भी शामिल थे। इस दौरान लोगों को जैसे ही पता चला तो वह भी वहां पहुंच गए। इस दौरान लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। साथ ही वीडियो भी बना रहे थे। दरअसल, हाथियों के आने की खबर से ग्रामीणों को लगी तो वह हाथी के देखने के लिए जंगल की तरफ आने लगे। ग्रामीणों की भीड़ को वन विभाग भी नहीं संभाल सका। एक ग्रामीण हाथियों के झुंड को देख भागने लगा, जिससे वह गड्ढे में जा गिरा। उसे गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीण घायल को तुरंत गांव से बस्ती लेकर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की पहचान रेकी रामपुर बस्ती के रहने वाले रामकुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों के साथ वो भी हाथियों के झुंड को देखने गया था। हाथियों के झुंड में नन्हे शावक भी शामिल है। जब हाथी ने हुंकार मारते हुए दौड़ाया है तो सभी भाग गए व हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मुस्तैद है।

अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्यवाही, 6 ट्रैक्टर जप्त

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत तथा ईट परिवहन में कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध रेत परिवहन करते पाये जाने पर 06 ट्रैक्टरों को जप्त किया गया है।

जिला खनिज अधिकारी प्रमोद नायक ने बताया कि जप्त 06 ट्रैक्टरों में सीतामणि से 1 ट्रैक्टर, बरबसपुर से 1 ट्रैक्टर, भिलाईखुर्द से ईंट भरे हुए 1 ट्रैक्टर जप्त किया गया है। तीनों को कोतवाली थाना में अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार से कुदुरमाल से 1 ट्रैक्टर जप्त कर मानिकपुर चौकी में, तरदा से 1 ट्रैक्टर तथा भैंसामुड़ा से 1 ट्रैक्टर को जप्त कर उरगा थाना में अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज अधिकारी ने बताया कि जप्त किए गए अवैध रेत और ईंट परिवहन पर एमएमडीआर एक्ट के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

विधायक भसीन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है. भसीन कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह समेत तमाम नेताओं ने उनका हालचाल जाना हैं। भाजपा विधायक को यूरिन इंफेक्शन और न्यूरो सम्बंधित बीमारी की वजह से रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इसकी सूचना भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलते ही अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं अब उनकी तबियत में सुधार न होने पर डॉक्टरों की सलाह पर एयर एंबुलेंस से गुड़गांव मेदांता हास्पिटल ले जाने की तैयारी की आज रही है, जिसके लिए परिजनों भी मंजूरी दी हैं.सीएम भूपेश बघेल ने भी परिजनों से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम जाना है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, एवं भाजपा विधायक भी परिजनों से सम्पर्क में हैं।

के-वाइसी अपडेट के लिए महिला से लाखों की ठगी

दुर्ग। मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ठगी की शिकार हो गई। महिला को अज्ञात कॉलर का फोन आया और केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा गया। महिला का खाता बेंगलुरू की शाखा में है और वह कोरोना काल से वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है। महिला केवाईसी के झांसे में आ गई और भेजे गए लिंक पर क्लिक कर दिया। महिला के खाते से एक दो नहीं पूरे 3 लाख 94 लाख 772 रुपए कट गए। जैसे ही महिला को ठगी का अहसास हुआ वह मोहन नगर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मोहन नगर पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थिया शानू लोहरा बैंगलोर मे काम करती है जहां उनका एचडीएफसी बैंक शाखा बेलन्दुर बैंगलोर मे बचत खाता क्रमांक 17561140002318 एवं एचडीएफसी.बैंक शाखा बनेरगट्टा बैंगलोर मे बचत खाता क्रमांक 50100119526500 है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के तहत वह अपने निवास मकान नं 22 मोहन नगर दुर्ग मे रहते हुए कार्य कर रही है।

जपं उपाध्यक्ष के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा ने जनपद पंचायत कोरबा के उपाध्यक्ष श्रीमती कौशिल्या बाई वैष्णव के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के सम्मिलन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी में परिवर्तन किया है। सम्मिलन की अध्यक्षता के लिए अब संयुक्त कलेक्टर सेवा राम दीवान को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने इस प्रयोजन हेतु डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार खाण्डे को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। 06 फरवरी से 03 मार्च तक डिप्टी कलेक्टरों के ऑफलाइन मोड में परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण मनोज कुमार खाण्डे डिप्टी कलेक्टर को कार्यमुक्त किया गया है। इस प्रयोजन अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाये गये सम्मिलन की अध्यक्षता के लिए संयुक्त कलेक्टर सेवा राम दीवान को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का सम्मिलन 09 फरवरी 2023 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा के सभा कक्ष में आहुत किया जाएगा।

बुधवारी पार्किंग क्षेत्र से अवैध कब्जे को हटाया निगम अमले ने

कोरबा। बुधवारी बाजार के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल पर किए जा रहे अवैध कब्जे को निगम अमले ने हटा दिया, इसके पूर्व भी उसी स्थल पर अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया गया था। अमले ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही संबंधित लोगों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अवैध कब्जे का प्रयास न करें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बुधवारी बाजार के सामने सड़क के दूसरी ओर खाली जमीन को पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, जहाँ पर बुधवारी बाजार पहुंचने वाले लोगों को वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उक्त पार्किंग क्षेत्र में कतिपय लोगों द्वारा दीवाल खड़ी कर बेजा

कब्जा किया जा रहा था। अवैध कब्जे की जानकारी प्राप्त होते ही आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के अतिक्रमण दस्ते को तत्काल अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए, जिस पर अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा तथा अवैध कब्जे को हटाया। संबंधितलोगों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अतिक्रमण का प्रयास न करें, एक बार पहले भी अवैध कब्जे का प्रयास किया गया था, जिसे हटा दिया गया था, अब यदि पुनः अतिक्रमण किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार घंटाघर में मितानिनों द्वारा बोर्ड आदि लगाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे भी अतिक्रमण दस्ते ने मौके पर हटा दिया।

सड़क पर सब्जी दुकानों को हटाया गया - कोसाबाड़ी मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे कतिपय सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी की दुकानें लगाकर व्यवसाय किया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है, सड़क पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित होती है तथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। निगम अमले ने इस पर कार्यवाही करते हुए सड़क के किनारे लगाई गई इन सब्जी की दुकानों को हटाया तथा संबंधित व्यवसायियों को कड़ी हिदायत दी कि वे सड़क पर सब्जी, फल आदि की दुकान न लगाएं, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

अवैध कब्जे पर सतर्क नजर - आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ ही जोन कमिश्नर्स, जोन प्रभारी एवं निगम के मैदानी अमले व अन्य अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अवैध कब्जे व अतिक्रमण पर सतर्क नजर रखें तथा जहाँ कहीं भी अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा हो, उस पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। आयुक्त श्री पाण्डेय ने आमजन से भी कहा है कि शासकीय जमीनों, सार्वजनिक स्थानों में अवैध कब्जा व अतिक्रमण का प्रयास न करें।

आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का परिणाम दिखने लगा है : रेखचंद जैन

जगदलपुर। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों का परिणाम अब दिखाई देने लगा है माता गुड़ियों एवं देव गुड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप आज हर गांव में पक्की माता गुड़ी तैयार हो गई है एवं सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ है उन्होंने कहा की मेला मंडई हमारी आस्था और संस्कृति है इसे सहेजना हम सब का कर्त्तव्य है आज की पीढ़ी शहरीकरण एवं आधुनिकता में अपनी संस्कृति से दूर हो रही है उन्हें

अपनी जड़ों से जोड़ने का सार्थक प्रयास हम सभी लोगों को करना चाहिए

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ जनपद सदस्य एवं ब्लाक अध्यक्ष नीलू राम बघेल, जनपद सदस्य धनसिंग बघेल, सरपंच धरम बघेल वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, महामंत्री हेमु उपाध्याय विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, वरिष्ठ नेता चैतुराम मराई ,मानसिंग नाग,लेम्पस अध्यक्ष सामनाथ नाग, लोकेश सेठिया विनोद सेठिया,हरिहर सेठिया,धनर मांझी, गणेश सेठिया, राधामोहन दास,सोमारू मांझी ,जगबन्धु मांझी समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

किसी भी हाल में तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं : कुशवाहा

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुके उपेन्द्र कुशवाहा लगातार पार्टी और नेताओं पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अब साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी सूरत में राजद नेता तेजस्वी यादव का नेतृत्व कभी भी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें दिल से फैसला लेने की मांग की। लालूराज की याद दिलाते हुए उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश, राजद से डील जदयू को खत्म कर देगी। इसलिए आप दूसरी की सलाह के बजाय अपने दिल से काम कीजिए। अगर किसी तरह की डील राजद से हुआ है तो उसे तुरंत खत्म कीजिए और अगर कोई डील नहीं हुआ है तो आप खुद इसका खंडन कीजिए। उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार एवं पार्टी में लवकुश समीकरण का ध्यान रखते हुए किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। अगर उपेन्द्र कुशवाहा का चेहरा ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं। किसी दूसरे अति पिछड़ा नेता को बड़ी जिम्मेदारी दीजिए।

मुझे राहुल की मानसिक आयु पर सदैव संदेह होता है: शिवराज

भोपाल। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता पर हमलावर है। बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस सांसद पर हमला बोला है। भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी मानसिक आयु पर सवाल किया है। सीएम ने कहा, मुझे राहुल की मानसिक आयु पर सदैव संदेह होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बातें कही जाती हैं उन पर चर्चा होती है लेकिन अभिभाषण पर एक बात नहीं की और वह उद्योगपतियों के बारे में बोलते रहे। बीते मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए गांधी ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडाणी के कारोबारी भाग्य और उनकी निजी संपत्ति में भारी वृद्धि को 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से जोड़ा था। उन्होंने अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।

मेघालय में टीएमसी-एनपीपी कार्यकर्ताओं में झड़प

शिलांग। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम चार लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एफआर खारकोंगोर ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तीन कंपनियों को जिले में तैनात किया गया है। मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। पुलिस के मुताबिक, घटना फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के चारबतापारा गांव में मंगलवार रात करीब 10:45 बजे हुई। टीएमसी में शामिल होने वाले एनपीपी के पूर्व विधायक एसजी एस्टामुर मोमिनिन रात करीब नौ बजे अपने रिश्तेदार के घर दावत में शामिल होने के लिए गांव आए थे। इसके बाद एनपीपी के समर्थकों का एक समूह वहां गया और हंगामा किया और कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों पर हमला किया।

महबूबा मुफ्ती को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को जम्मू-कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के विरोध में बुधवार को संसद तक मार्च निकालने से रोक दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महबूबा की रेलवे भवन से संसद तक मार्च करने की योजना थी। वह जम्मू-कश्मीर प्रशासन की बुलडोजर नीति के बारे में विपक्षी दलों को सूचित करना चाह रही थी। दिल्ली पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें जंतर-मंतर ले जाया गया। महबूबा ने कहा कि हम विपक्षी दलों और केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर जनता के साथ हो रहे परेशानियों को बताने के लिए आए थे। अगर हम संसद नहीं जा सकते हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि हमें कहां जाना चाहिए। क्या सरकार चाहती है कि हम संयुक्त राष्ट्र में अपनी शिकायतों का निवारण करवाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कानून का कोई राज नहीं है और हम अपने दिल की बात कहने के लिए दिल्ली आए थे।

भाजपा नेताओं की जासूसी करा रहे केजरीवाल

नई दिल्ली। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उसके नेताओं की जासूसी करा रही है। इसके लिए सरकार के नियंत्रण में एक विशेष यूनिट बनाई गई है, जिसके अधिकारियों को केवल भाजपा के नेताओं की जासूसी करने के पीछे लगाया गया है। पार्टी इस बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करने पर भी विचार कर रही है। चूंकि, इस कथित जासूसी यूनिट की स्थापना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ही एक मंत्रालय के अधीन की गई थी, इसकी जांच की आंच सिसोदिया पर भी आ सकती है। यानी शराब घोटाले के बाद इस मामले में भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में अपनी स्थापना से ही अराजकता के साथ काम करती रही है। अब इसके प्रमाण भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति गलत नीयत से काम करती है और उनके दमन में विश्वास करती है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए बोले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकल्प से सिद्धी तक की यात्रा का खाका खींचा गया

कुछ निराशावादी लोग देश की प्रगति स्वीकार नहीं कर पा रहे: मोदी

नईदिल्ली। बीते कुछ दिनों से अडानी विवाद को लेकर गतिरोध का सामने करने वाले दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही देखने को मिली और अधिकांश विपक्षी दलों ने संसदीय कार्यवाही में भाग लिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी विवाद को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उनके आरोपों पर पलटवार भी किया। बुधवार को भी संसद में गरमागरम बहस जारी रही और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच या आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए। विपक्ष के तमाम सवालों के बाद अब बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले भी मुझे कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद के साथ-साथ राष्ट्रपति का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन किया। उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की बहन-बेटियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का अवसर भी। आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है और उनका जो विश्वास बढ़ा है। इसके लिए ये सदन और देश उनका आभारी है।

पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत में नई संभावनाएं हैं। कइयों को यह बात समझने में देर लग जाएगी लेकिन भारत सप्लाई चेन के मामले में आगे बढ़ गया है। भारत मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है। दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। निराशा

में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और परिश्रम उपलब्धि उन्हें नजर नहीं आ रही। पिछले नौ वर्ष में भारत में 90 हजार स्टार्टअप आए हैं। आज स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम देश की टियर-3 शहरों तक पहुंच चुका है। इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने। एक यूनिकॉर्न यानी छह-सात हजार करोड़ से ज्यादा का मूल्य। आज भारत दुनिया में मोबाइल बनाने में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्रियों के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि यहां चर्चा में हर किसी ने अपने अपने आकड़ें और तर्क दिए... अपनी रूचि, प्रवृति और प्रकृति के अनुसार अपनी बातें रखी और जब इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता, योग्यता और इरादा है। देश इन सभी का मूल्यांकन करता है। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा ईकोसिस्टम, समर्थक उछल रहे थे। और खुश होकर कहने लगे, ये हुई न बात! शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह-कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, जनजातीय समुदाय के प्रति नफरत भी दिखाई दी है और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है, लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गईं तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, वो सच बाहर आ ही गया। राष्ट्रपति का भाषण हो रहा था तो कुछ लोग कत्री भी काट गए। एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति का अपमान भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत अपनी अधिकांश समस्याओं के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है।

जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रहकर स्वीकार किया गया है। यानी, राष्ट्रपति के भाषण के प्रति किसी को ऐतराज नहीं है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा था- देश की एक बड़ी आबादी ने जिन सुविधाओं के लिए दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिलीं। देश सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की समस्याओं से मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति उसे अब मिल रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि सदन में हंसी-मजाक, टीका-टिप्पणी, नोंक-झोंक होती रहती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं। गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों व हमारे पड़ोस में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे समय में कौन हिंदुस्तानी गौरव नहीं करेगा कि उनका देश दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी है। 100 साल में आई हुई यह भयंकर महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बंटा हुआ विश्वइस स्थिति में भी, संकट के माहौल में, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास और गौरव से भर रहा है।

प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मोड में होते हैं : कांग्रेस अध्यक्ष

संसद में विपक्ष अदाणी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जिसके चलते संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा हो रहा है। हालांकि इस हंगामे के बीच कुछ ऐसे पल भी आए, जब विपक्ष के नेता की बात पर प्रधानमंत्री मोदी समेत सदन के सभी सदस्य खूब हंसे। बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिकायती लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री सदन में कम दिखाई देते हैं। जब संसद चलती है तो वह इधर ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मोड में होते हैं। इधर संसद चल रही है और उधर मेरे संसदीय क्षेत्र कलबुर्गा में चले गए। खड़गे ने कहा कि अरे भई मेरा एक ही संसदीय क्षेत्र है और आपको वही मिल रहा है। और संसदीय क्षेत्र में एक भी नहीं दो-दो मीटिंग कर रहे हैं! खरगे के इतना कहते ही सदन में हंसी के ठहाके गूंज उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़गे की बात पर हंस पड़े। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए कहा कि मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं। राज्यसभा में अदाणी मामले पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े शायराना भी हो गए और बोले कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीं पर चांद सितारों की बात करतें हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं! बड़ा हसीन हैं उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, मिली कमान तो अटकी नजर खजानों पर, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं! गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। अपने भाषण के अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदाणी मामले की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) का गठन कर जांच कराने की बात कही। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की इस शायरी पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि खड़गे की बात सुनकर मेरे अंदर भी शायर जाग गया है। उन्होंने कहा उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।

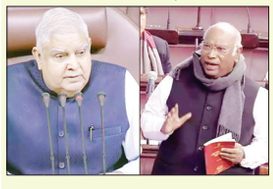

खड़गे के बयान पर राज्यसभा में भारी हंगामा

कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। खड़गे ने पूछा, प्रधानमंत्री को सदन में अधिक समय बिताना चाहिए। पीएम इतने चुप क्यों हैं? खरगे ने अडानी मुद्दो को लेकर भी जेपीसी जांच की मांग की। वहीं खड़गे के बायन पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति ढ़ाई साल में 13 गुना बढ़ गई। 2014 में 50,000 करोड़ की थी वह 2019 में एक लाख करोड़ की हो गई। अचानक ऐसा क्या जादू हुआ कि दो साल में 12 लाख करोड़ बढ़ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है ही जिसे वे (बीजेपी) नहीं मानते हैं। जिसका जवाब देते हुए राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि वे विदेश रिपोर्टों(हिंडनबर्ग रिपोर्ट) पर बातें कर रहे हैं, यह तो कांग्रेस का तारीका है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि इनके खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते हैं उनकी संपत्ति ही देखें कि 2014 में इनके नेता की कितनी संपत्ति थी और आज कितनी है। मल्लिकार्जुन खरगे के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बिठाए जाने और इस (अडानी मामले) की जांच पर जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) तब बैठती है जब आरोप सिद्ध हो जाए। जब सरकार पर आरोप लगता है तब संयुक्त संसदीय समिति बिठाई जाती है किसी निजी व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं।

खेल
प्रमुख समाचार

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का आज से नागपुर में आगाज

नागपुर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होने वाली है। इस सीरीज में चार टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल ने संकेत दिए हैं कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम तीन स्पिन गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा, हम भारत में खेल रहे हैं, जहां पिच में टर्न होता है। इसलिए तीन स्पिनरों को टीम में शामिल करने की इच्छा होगी।

बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान स्पिनरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय पिचों के मिजाज को देखते हुए अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल की गेंदबाजी सीरीज का नतीजा तय कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास नाथन लियोन और स्वेपसन जैसे फिरकी गेंदबाज हैं जिनसे टीम इंडिया को बचना होगा। केएल राहुल ने ये भी बताया कि भारतीय टीम स्पिन खेलने के लिए खास तैयारी कर रही है। राहुल ने कहा, हमने स्पिन खेलने पर काम किया है। हम जानते हैं कि भारत में पिचें कैसी होंगी और क्या उम्मीद करनी चाहिए। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए, हम अभ्यास कर रहे हैं। हमें एहसास है कि हम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलना चाहते हैं। लेकिन हम एक समय में एक मैच पर ही ध्यान रखना चाहते हैं।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएस भरत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी।

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, एश्टन एगर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूती के साथ बंद

नईदिल्ली। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिली रही है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में अच्छी तेजी रही है। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा का उछाल है। बीएसई सेंसेक्स 377.75 अंक यानी 0.63 फीसदी चढ़कर 60,663.79 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। इसी तरह निफ्टी 150.20 अंक यानी 0.24 फीसदी की तेजी के साथ 17,871.70 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स में आज आईटी, फार्मा और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी है। अन्य सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं। हैवीवेट शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आज बाजार ने स्वागत किया। आज के कारोबार में अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 14 फीसदी तक मजबूत हुआ है।

आरबीआई ने रेपो रेट में छठी बार बढ़ोतरी की

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम आदमी पर एक बार भी अपना चाबुक चला दिया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में करीब 25 आधार अंक (बेसिस प्वाइंट) अथवा 0.25 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। पिछले एक साल से भी कम समय में आरबीआई ने करीब छठी बार कर्ज को महंगा करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। आरबीआई के इस कदम से रेपो रेट बढ़कर करीब 6.50 फीसदी तक पहुंच गई है। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। वहीं, अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान रखा गया है।

खुदरा महंगाई दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 5.3% का अनुमान

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अगले वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा खुदरा महंगाई नरम पड़कर 5.3 फीसदी पर आने का अनुमान जताया। चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 6.5 फीसदी के स्तर पर रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष का अनुमान केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर दो प्रतिशत के घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने के लक्ष्य से अधिक है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेश द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा कि 'आयातित' महंगाई कम रहने से अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आएगी। हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति अब भी ऊंची बनी हुई है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 6.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था। सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट तथा भारत की कच्चे तेल की खरीद 95 डॉलर प्रति बैरल रहने के आधार पर केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को कम किया है।

महिंद्रा ने शुरू की सस्ती एसयूवी की डिलीवरी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एसयूवी निर्माता महिंद्रा ने अपनी सस्ती एसयूवी की डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। महिंद्रा की ओर से थार एसयूवी के रियर व्हील ड्राइव वैरिएंट की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। कंपनी ने थार 4×2 को हाल में ही लॉन्च किया था। इससे पहले इसे सिर्फ 4×4 वैरिएंट में ही ऑफर किया जाता था। थार के सस्ते वैरिएंट 4×2 को लॉन्च करने के बाद से ही कंपनी को इसके लिए काफी ज्यादा बुकिंग मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को इस वैरिएंट के लिए इतनी ज्यादा बुकिंग मिल गई हैं कि अब इसका वेटिंग पीरियड बढ़कर करीब 18 महीने तक पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी700 जैसी एसयूवी की भी बिक्री करती है, और उनके लिए भी बाजार में काफी डिमांड है। जिसके कारण कम कीमत वाली थार के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना भी संभव नहीं है।

भारत की आर्थिक नीतियों का वर्ल्ड इकोनामी फोरम पर बजा डंका

प्रह्लाद सबनानी

स्विजरलैंड के दावोस नामक स्थान पर 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) की 43वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। विश्व आर्थिक मंच एक गैरलाभकारी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है जो निजी एवं सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से काम करती है। विश्व आर्थिक मंच की प्रतिवर्ष होने वाली बैठक में विश्व के तमाम बड़े राजनेता, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संस्कृति और समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते हैं। इस बैठक में वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, राजनैतिक, औद्योगिक, आदि क्षेत्रों से सम्बंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है एवं इन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच को लगभग 1000 सदस्य कम्पनियों, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जिनका टर्नओवर 5 अरब डॉलर से अधिक होता है, द्वारा विभिन्न आयोजनों के लिए फण्ड उपलब्ध कराया जाता है। दावोस में आयोजित वर्ष 2023 की बैठक में चर्चा हेतु मुख्य विषय चुना गया था बंटे हुए विश्व में सहयोग की भावना जागृत करना।

विश्व आर्थिक मंच को यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल श्री गुटेरस ने अपने विशेष उद्बोधन में बताया कि विश्व इस समय कुछ टुकड़ों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है एवं एक तरह से पूरा विश्व ही आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। कई देशों में मंदी की आहट सुनाई दे रही है एवं आगे आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की दर धीमी पड़ने की सम्भावना बहुत बढ़ गई

हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए अपने जीवन निर्वहन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है एवं करोड़ों नागरिकों के लिए तो यह असहनीय स्तर तक पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चैन की परेशानियां, विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद से, बहुत बढ़ गई हैं। इसी प्रकार, एनर्जी संकट, मुद्रास्फीति, मंदी की आहट, ब्याज दरों का लगातार बढ़ते जाना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत हल करना आवश्यक है। पर्यावरण का संकट भी मुंह बाए खड़ा है, ग्रीन हाउस गैस का विस्तार लगातार तेजी से अभी भी हो रहा है तथा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्स) और समस्त देशों की, वैश्विक तापमान में केवल 1.5 डिग्री की वृद्धि होने देने पर, प्रतिबद्धता की ओर अभी तक विशेष रूप से विकसित देशों का ध्यान नहीं जा रहा है। यदि समय रहते समस्त देशों ने इस अति गम्भीर रूप लेती समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो बहुत सम्भव है कि इस समस्या को फिर हम हल ही नहीं कर पाएंगे और एक अनुमान के अनुसार वैश्विक तापमान में 2.8 डिग्री की वृद्धि दृष्टिगोचर होगी, इसे विश्व सहन ही नहीं कर पाएगा।

दावोस में ही एक अन्य कार्यक्रम में वैश्विक सलाहकार संस्था अर्नस्ट एंड यंग (ई वाय) ने एक विशेष प्रतिवेदन इंडिया एट 100- रीयलाईजिंग द पोटेंशियल आफ 26 ट्रिलियन डॉलर इकानोमी नाम से जारी कर बताया है कि कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध एवं वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी, भारत के अमृत काल के दौरान, वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 26 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा।

शीघ्र ही, वर्ष 2028 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2036 में 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 में प्रत्येक भारतीय की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 15,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी, ये आज के स्तर से 7 गुना से भी अधिक है। वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। दरअसल भारत में भारी क्षमताएं मौजूद हैं और आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति पूरे वैश्विक आर्थिक मंच को प्रभावित करने जा रही है।

आंतरिक युद्ध की तैयारी कर रहा पाकिस्तान

बिक्रम उपाध्याय

30 जनवरी को पेशावर की पुलिस ऑफिसर कॉलोनी मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 100 से अधिक पुलिस के लोग मारे गये थे। यह हमला इतना भीषण था कि पूरा पाकिस्तान दहल गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि अगर पुलिस ही आत्मघाती हमलों से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी समूह तहरीक ए तालिबान ने ली थी, लेकिन बाद में वह मुकर गया। फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरानों का मानना है कि यह हमला टीटीपी से ही जुड़े जमात उल अहरार ने किया था। इसके बाद 3 फरवरी को पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटीज कमिटी की मीटिंग में यह तय किया गया कि अब टीटीपी से कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि पूरी क्षमता से आतंकवाद को कुचलने की कार्रवाई होगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता स्वयं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की और पाक फौज के मुखिया जनरल आमिर मुनीर भी शामिल हुए। दरअसल टीटीपी पाकिस्तान की ही देन है। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब उनकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन तालिबान लड़ाकों के खिलाफ चलाया था। अमेरिकन आर्मी के हमले से बचने के लिए तालिबानी लड़ाके भाग कर स्वात की घाटी में आ गए जहां उनके जैसे ही कबायिलियों ने उन्हें ना सिर्फ शरण दी, बल्कि उनके साथ अमरीकी फौज के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध में हिस्सा भी लिया। अमेरिका को यह बात समझ में आई और उसने कीमत देकर पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया। पाकिस्तान को इसके लिए अमेरिका ने 32 अरब डॉलर दिए। बाद में अमेरिका ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने उनके साथ डबल गेम कर दिया। उन्होंने एक तरफ तालिबान के सफाये के लिए अमरीका से पैसे लिए और दूसरी तरफ उन्होंने टीटीपी जैसे संगठन को जिंदा किया। टीटीपी का गठन पाकिस्तान में ही 2007 में हुआ और उसका पहला प्रमुख बना बैतुल्लाह महसूद। तब से यह संगठन पाकिस्तान में तबाही मचाता रहा है और अभी तक इसके साथ लड़ते हुए पाकिस्तान के 85 हजार लोग मारे जा चुके हैं। 2020 में जब अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ और यह तय हो गया कि अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फौजी निकल जाएंगे, तो टीटीपी को खुला मैदान मिल गया। अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए जमा किए सभी आधुनिक हथियारों के साथ टीटीपी पाकिस्तान में सक्रिय हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने को अल्लाह का करम बताने वाले इमरान खान को तब यह अहसास हो गया कि यदि टीटीपी को नहीं संभाला गया तो वह उनके लिए ही खतरा बन जाएगा। चूंकि खैबर पख्तुनख्वा में इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ की सरकार थी, इसलिए उनके पास खबरें आने लगी कि टीटीपी के लोग अब अपने इलाकों में सक्रिय हो गए हैं और वहां के लोगों से जबरन वसूली करने लगे हैं। मई 2021 में इमरान खान ने तालिबान नेताओं की मध्यस्थता में टीटीपी से बातचीत की। इसी दौरान पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज हमीद की अध्यक्षता में उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल काबुल भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल में जनरल फैज के अलावा खैबर पख्तुनख्वा के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि और कुछ मुस्लिम उलेमा भी गए। कहते हैं कि जनरल फैज इमरान खान के बेहद करीबी थे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वाहवाही के लिए ही काबुल का दौरा किया था। क्योंकि वहां से लौटने के बाद उन्होंने चहकते हुए अंदाज में कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने भी यह ऐलान किया कि जो भी टीटीपी का आतंकवादी अपना हथियार सौंप देगा और वह पाकिस्तान के संविधान के अनुसार चलना स्वीकार कर लेगा उसे आम माफी दे दी जाएगी। लेकिन उनकी घोषणा के तुरंत बाद ही टीटीपी ने एक पत्र जारी कर यह साफ कर दिया कि उनका माफी मांगने का सवाल ही नहीं।

दल बदलुओं का जैसा दल वैसी विचारधारा

उमेश चतुर्वेदी

रामचरितमानस के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली चौपाई पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य असल में अपने दल का वैचारिक ढोल बजा रहे हैं। जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी का राजनीतिक चोला पहना है, तब से वे प्रखर समाजवादी और हिंदुत्वविरोधी नजर आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी से पहले जब वे भारतीय जनता पार्टी में थे तो हिंदुत्व के पैरोकार थे। सनातनी संस्कृति उन्हें दुनिया की महानतम संस्कृति लग रही थी। उसके पहले जब वे बहुजन समाज पार्टी में थे, उनकी नैतिकता वहां के सुप्रीमो के इर्द-गिर्द ही घूमती थी। यह चलन सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य तक ही सीमित नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक पेड़ों पर उछल-कूद करने वाले हर राजनेता की स्थिति ऐसी ही है।

लेकिन क्या रामचरित मानस पर सवाल उठाने और उसे तमाम बहानों से लांछित करने की मौर्या या चंद्रशेखर की कोशिश के पीछे सिर्फ यही बात है? रामचरित मानस पर पहले सवाल उठाया बिहार के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के कथित पढ़े-लिखे नेता चंद्रशेखर ने। अब भी वे डंके की चोट पर रामचरितमानस और सनातनी संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं। यह संयोग है कि बिहार की राजनीति का प्रथम यादव परिवार माना जाने वाला लालू कुनबा उत्तर प्रदेश के प्रथम यादव परिवार का रिश्तेदार है। दोनों में कम से कम विचारधारा के स्तर पर सहज साम्यता है। लालू परिवार की नजर में उसके कार्यकर्ता चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाकर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। खुलकर लालू परिवार ने उन्हें न तो अब तक टोका और ना ही ऐसी बयानबाजी से बाज आने के लिए ताकीद की है।

कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश के समाजवादी परिवार के नए अनुयायी स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है। वे भी रामचरित मानस को गालियों का उपहार दे रहे हैं, उनके उकसावे में कुछ लोग उस मानस की प्रतियां जला चुके हैं, जिसे सदियों से भगवत् पुस्तक का देवदर्जा हासिल है। यह दर्जा सिर्फ सवर्ण परिवारों के पूजाघरों तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बृहत्तर हिंदू समाज तक इसका प्रसार है। दिलचस्प यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी जब शुरू करते हैं तो लगता है कि उनके दलीय आका अखिलेश यादव उन्हें चेतावनी देंगे। क्योंकि उन्हें आनन-फानन में बुलावा मिलता है। लेकिन अखिलेश से मिलकर वे हंसते हुए बाहर निकलते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद एकबार फिर वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नामित कर दिए जाते हैं। साफ है कि रामचरित मानस पर सवाल उठाने का उन्हें इनाम भी मिलता है।

आजादी के आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य सामाजिक उत्थान भले ही रहा हो, लेकिन अब वह उद्देश्य सत्ता प्राप्ति तक सिमट गया है। सामाजिक उत्थान इस सत्ता प्राप्ति का अत्यंत लघु हिस्सा है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता हासिल होती है, ज्यादा वोट हासिल होने से। इसके लिए पूरे साल राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों के जरिए दो काम करते रहते हैं, पहला अपने पारंपरिक वोट बैंक को संभाले रखना और नया वोटबैंक तैयार करना। इसके लिए वे जातीय और धार्मिक गोलबंदी और बाड़ेबंदी में लगातार सक्रिय रहते हैं। चंद्रशेखर की कुबोली हो या स्वामी प्रसाद मौर्य की गाली, दोनों राजनीति की इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। दोनों का उद्देश्य है अपने अपने दलों के वोट बैंक को और ज्यादा व्यापक बनाना और उसमें नए-नए हिस्सों को शामिल करना। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों दल और उनके ये दोनों वाचाल नेता किस तरह की गोलबंदी करना चाहते हैं?

दरअसल आज यह मान लिया गया है कि हिंदुत्व का पैरोकार और रखवाला सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमिहार और बनिया समुदाय आते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान से ही भारतीय समाज में ब्रिटिश सोच वाले कम्युनिज्म ने अपनी कोशिशों से यह नैरेटिव स्थापित कर दिया है कि इस देश में अतीत में जितना भी बुरा हुआ है, उसके वाहक सिर्फ और सिर्फ यही सवर्ण तबका ही रहा है। दिलचस्प यह है कि अपने निजी आर्थिक हितों के लिए समय-समय पर इन्हीं सवर्ण तबके के लोग भी इस नैरेटिव के बड़े पैरोकार रहे। याद कीजिए मंडलवाद के दौर को। उस दौर में सवर्ण समाज के खिलाफ बाकी सभी जातियों को गोलबंद करने में समाजवादी और वामपंथी राजनीति सफल रही थी।

लेकिन बाद में अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समाजवादी धारा के कुछ राजनीतिक नेता और दल अलग हुए और उन्होंने पिछड़े समाज में भी विभाजन किया। इसकी शुरूआत नीतीश कुमार ने बिहार से की। उन्होंने दलित नेताओं का असर कम करने के लिए दलितों में अति दलित और पिछड़े समाज की राजनीति में दरार डालने के लिए पिछड़ों मे अति पिछड़ों को अलग किया। इसी फॉर्मूले को किंचित बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभाव बढ़ाने में किया। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में अजेय समझा जाता रहा मुलायम कुनबा और बिहार का लालू परिवार राजनीति के मैदान में कमजोर पड़ने लगा। दोनों ही परिवारों को लगता है कि अगर एक बार फिर पिछड़ों के बीच खींची लकीर को अप्रभावी बना दिया जाय तो उनकी राजनीति सत्ता के मैदान में अक्षुण्ण बनी रह सकती है।

स्वामी प्रसाद मौर्य हों या चंद्रशेखर, दरअसल वे अपने-अपने दलों के मोहरे हैं। दोनों दलों को लगता है कि पिछड़ों के बीच खिंची राजनीतिक लकीर को मिटाया तभी जा सकता है, जब धर्म पर हमला किया जाए। जब ऐसा होगा तब प्रचलित नैरेटिव के मुताबिक सवर्ण समाज प्रतिरोध में खड़ा होगा और फिर इसके जवाब में पिछड़ी और दलित जातियों को सवर्णों के खिलाफ लामबंद करने में मदद मिलेगी। अगर एक बार ऐसा हो गया तो राजनीतिक राह आसान हो जाएगी।

लेकिन दल बदलकर सोच बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इकलौते नेता तो नहीं है। भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार गिरवाकर एकदिनी मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल पहले समाजवादी सोच के कांग्रेसी रहे, अब राष्ट्रवादी हैं। बहुजन समाज पार्टी में रहते वक्त भाजपा को ही कोसते रहे ब्रजेश पाठक अब भाजपा के कर्णधार हैं। सिद्धारमैया की राजनीति गैरकांग्रेसवाद से उफान चढ़ी, लेकिन अब वे उसी कांग्रेस का दक्षिण का चेहरा हैं। के चन्द्रशेखर राव कभी तेलुगू बिड्डा एनटी रामा राव के सहयोगी और कांग्रेस विरोधी थे, बाद में कांग्रेसी भये और अब अपनी पार्टी चला रहे हैं।

बहरहाल, इन नेताओं के सामने एक मजबूरी और है। जब तक ऐसे दलबदलू नेता चर्चा में नहीं आयेंगे, दल की विचारधारा के ज्यादा समर्पित नहीं दिखेंगे, इन्हें महत्व नहीं मिलेगा। मसलन उदितराज तब तक भाजपा में रहे एक शब्द कभी धर्म के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन जिस दिन लगा कि अब भाजपा टिकट भी नहीं देगी तो उन्हें हिन्दू समाज में जातिवाद दिख गया और भाजपा ब्राह्मणवादी पार्टी हो गयी।

प्रसंग — भविष्य की चिन्ता

मुस्लिम सन्त करमानी की बेटी उनसे बढ़कर थी। उसके सौन्दर्य और स्वभाव की कीर्ति सुनकर बादशाह ने अपने शहजादे के साथ उसके विवाह प्रस्ताव रखा। यद्यपि करमानी शाही खानदान से संबंधित थे, किन्तु वे नहीं चाहते थे कि बेटी का विवाह शाही खानदान में किया जाए। उन्होंने बादशाह के प्रस्ताव को ठुकराकर एक फकीर के साथ उसका निकाह कर दिया। बेटी जब अपने खविन्द के घर आयी तो उसे एक कटोरे में पानी और एक थाली में सूखी रोटी के टुकड़े ढंके हुए दिखाई दिये। उसने पति से घर पहुंचाने की प्रार्थना की। इस पर फकीर बोला मैं जानता था कि तुम सरीखी शाही खानदान की लडकी मुझ जैसे फकीर के साथ कभी बसर नहीं कर सकेगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे अब्बाजान से अपनी हालात बयान कर दियया था, लेकिन इसक बावजूद उन्होंने रजामन्दी दे दी थी। अगर मैं जानता की तुम मेरी हालात से वाकिफ नह हो, तो मै कभी राजी न हुआ होता। नहीं,नही, ऐसी बात नहीं लड़की बोली मैं तुम्हारी हालात के कारण घर नहीं जाना चाहती। मै तो अब्बाजान से इस बात की शिकायत करने जाना चाहती थी कि आपने तो यह कहा था कि आप मेरा निकाह खुदादोस्त और परहेजगार व्यक्ति के साथ करेंग, मगर मैने तो यह पाया कि मेरे खविन्द का तो अल्लाह पर भी भरोसा नहीं।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1757 राबर्ट क्लाइव ने अलीनगर संधि के जरिए कलकत्ता ञ्अब कोलकाताः को सिराजुदौला से लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके में शामिल कर लिया।
1824 उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध बांग्ला कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने ईसाई धर्म कुबूल किया।
1951 स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का कार्य शुरु।
1969 देश के छह राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा।
1971 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चांद पर भेजा गया अपोलो 14 अंतरिक्ष यान अपनी कार्यअवधि पूरी कर धरती पर वापस लौटा।
1975 रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 अंतरिक्ष में 29 दिन बिताने के बाद धरती पर लौटा।
2010 हैती में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 2,30000 होने का आधिकारिक ऐलान किया गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पैङ्गलोपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

अविचार करने से बन्धन और विचार (सद्विचार) करने से मोक्ष होता है। इसलिए सदैव विचार (सद्विचार) करना चहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है। इसलिए सदा जगत, जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार (चिन्तन) करना चाहिए। जीव भाव और जगद्भाव का निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा (जीव) से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है।

इसके पश्चात् पैङ्गल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा- मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइये। याज्ञवल्क्य बोले- वह तुम हो (तत्त्वमसि), तुम वह हो (त्वं तदसि), तुम ब्रह्म हो (त्वं ब्रह्मासि), मैं ब्रह्म हूँ (अहं ब्रह्मास्मि), ये महावाक्य हैं, जिन पर अनुसन्धान (विचार) करना चाहिए।

तत्त्वमसि में तत् पद सर्वज्ञत्व आदि लक्षण से युक्त, माया की उपाधि से युक्त, सच्चिदानन्द रूप, जगत् योनि (मूलकारण) रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अन्त:करण की उपाधि के कारण भित्रता का बोध होने से त्वं पद का आलम्बन लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है, इनका परित्याग कर देने से तत् और त्वं पदों का लक्ष्य (आशय) उस ब्रह्म से है, जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है।

तत्त्वमसि और अहं ब्रह्मास्मि इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता है। श्रवण किए हुए विषय के अर्थों का एकान्त में अनुसन्धान करना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णीत अर्थ रूप वस्तु में एकाग्रतापूर्वक चित्त का स्थापन निदिध्यासन कहलाता है। जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय में स्थिर हो जाती है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं।

उसमें (उस अवस्था में) आत्मगोचर वृत्तियाँ उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं, जो स्मरण के द्वारा अनुमानित होती हैं (अर्थात् जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है)। संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं।

इसके पश्चात् अभ्यास पटुता (परिपक्वता) प्राप्त हो जाने पर सतत सहस्त्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। इसीलिए योगज्ञाता समाधि को धर्ममेघ कहते हैं। इसके माध्यम से सम्पूर्ण वासनाजाल नि:शेष (समाप्त) हो जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित कर्म समूल विनष्ट हो जाते हैं।

क्रमशः

समाज के लिए समर्पित रहे बाबा आम्टे

मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें बाबा आम्टे के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित गरीबों के सशक्तिकरण के लिए काम किया था। चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए बच्चे से, बाबा आमटे ने अपना जीवन समाज के दलित लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह महात्मा गांधी के शब्दों और दर्शन से प्रभावित थे और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए अपने सफल कानून अभ्यास को छोड़ दिया। बाबा आमटे ने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और वे आदर्श वाक्य 'वर्क बिल्ड्स' के साथ आगे बढ़े; दान नष्ट हो जाता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए बाबा आम्टे ने आनंदवन (वन का आनंद) का गठन किया। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) जैसे अन्य उग्र सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से भी जुड़े थे। अपने मानवीय कार्यों के लिए, उन्हें 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले।

बाबा आमटे के नाम से मशहूर मुरलीधर देवीदास आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट में हुआ था। वह देवीदास और लक्ष्मीबाई आमटे के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पिता देवीदास स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश प्रशासन और वर्धा जिले के एक अमीर ज़मींदार थे। एक संपन्न परिवार की पहली संतान होने के नाते, मुरलीधर को बहुत स्नेह के बीच पैदा हुआ था और बचपन से ही उनके माता-पिता द्वारा एक भी बात से इनकार नहीं किया गया था। उनके माता-पिता प्यार से उन्हें 'बाबा' कहते थे। 2007 में, बाबा आमटे को ल्यूकेमिया का पता चला था। एक साल से अधिक समय तक पीड़ित रहने के बाद, अमटे ने 9 फरवरी, 2008 को आनंदवन में अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। महान आत्मा की मृत्यु पर दुनिया भर के कई प्रसिद्ध लोगों ने शोक व्यक्त किया। बाबा आमटे के पार्थिव शरीर को दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया।

चुनाव चुनौतियों के लिए कांग्रेस की तैयारी

आदिति फडणीस

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत से उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे राजीव शुक्ला ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस का अगले सभी चुनावों में उभार होगा। कांग्रेस सांसद शुक्ला को वर्ष 2022 के हिमाचल प्रदेश चुनाव में पार्टी प्रभारी बनाकर भेजा गया था जहां कांग्रेस चुनाव जीत गई और पार्टी ने सरकार बना ली। शुक्ला ने बताया, 'हम कर्नाटक (विधानसभा चुनाव) जीतेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हमें सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश में अच्छी संभावनाओं के साथ हम चुनाव जीतेंगे। इसके बाद हम हरियाणा में भी जीत हासिल करेंगे।' शुक्ला का भरोसा उन असंख्य संकेतों में है जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकप्रियता में कमी आने की ओर इशारा करते हैं। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कांग्रेस 2024 की चुनौती के लिए खुद को आंतरिक रूप से तैयार कर रही है। तैयारी का एक पहलू संगठन को मजबूत बनाना और दूसरा उन विचारों को उभारना है जिन पर पार्टी विश्वास करती है। नवंबर में कांग्रेस कार्यबल की एक बैठक नई दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर हुई जिसे पार्टी का हर सदस्य अपना वॉर रूम कहता है। इस कार्यबल का गठन अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी ने राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के तीन दिवसीय बड़े सम्मेलन से ठीक पहले किया था। सोनिया ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले 'राजनीतिक चुनौतियों' से निपटने के लिए ही एक 'सशक्त कार्यसमूह' की घोषणा की थी। हालांकि, पार्टी अध्यक्ष के चुनावों की वजह से आखिरकार नवंबर में मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में कार्यबल की पहली बैठक हुई। जहां तक 'भारत जोड़ो यात्रा' का संबंध है तो उदयपुर के चिंतन शिविर में ही इसका विचार दिया गया था। लेकिन इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते 'हाथ से हाथ जोड़ो' नाम के एक नए सार्वजनिक जनसंपर्क कार्यक्रम की घोषणा की जिसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मकसद 2024 के संसदीय चुनावों से पहले मौजूदा सरकार के कथित कुशासन को उजागर करना है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कहा कि नया अभियान पूरी तरह से राजनीतिक अभियान होगा जबकि 'भारत जोड़ो यात्रा' में सामूहिक मंच के माध्यम से बुनियादी मुद्दों को उठाया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भारत के इस सबसे लंबे पैदल मार्च का प्रमुख चेहरा थे जबकि 'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान की जमीनी शुरुआत पार्टी की राज्य इकाइयों के माध्यम से शुरू की जाएगी। पार्टी समय-समय पर आरोप पत्र जारी करेगी जैसा कि उसने 2004 के आम चुनाव से पहले वर्ष 2003 में किया था और जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। आरोप पत्र में रोजमर्रा की आजीविका के मुद्दे भी उठाए जाएंगे।

वेणुगोपाल ने इसकी मिसाल देते हुए कहा, 'इस देश में 35 लाख नौकरियां चली गई हैं। मई 2014 में पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपये, डीजल की कीमत 55.49 रुपये और कच्चे तेल की कीमत 105.71 डॉलर प्रति बैरल थी। जनवरी 2023 में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये थी। अब यह फिर से बढ़ गया है। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। किसान बहुत मुश्किल स्थिति में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी किसान राहुल के पास आए और उन्होंने शिकायत की कि वे पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतों पर इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं।' 'हाथ से हाथ जोड़ो' यात्रा के दौरान इस और अन्य रोजी-रोटी के मुद्दे पर खुले तौर पर राजनीतिक तरीके से बात की जाएगी। लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए, पार्टी की राज्य इकाइयों को फिर से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से एक कठिन काम है, हालांकि पार्टी इसके लिए तैयार दिख रही है।

पार्टी का महाधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा, जहां बड़े पैमाने पर संगठनात्मक बदलाव से जुड़े फैसले किए जाने की उम्मीद है। सत्र में यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव आयोग जैसे प्रमुख पार्टी निकायों का गठन चुनावों के माध्यम से किया जाना चाहिए या पार्टी अध्यक्ष के मनोनयन से किया जाए क्योंकि ऐसी परंपरा भी रही है। पार्टी के भीतर चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं और इसमें आंतरिक स्तर पर थोड़ी हलचल भी है लेकिन राहुल और सोनिया के पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाने का फैसला करने के साथ ही, पार्टी में उनके आलोचकों के पास आलोचना करने के लिए कोई एक भी मुद्दा नहीं बचा है। इस बीच, कर्नाटक की तरह ही जो राज्य इकाइयां सत्ता में वापसी करने की संभावना देख रहीं हैं वे नए बदलाव पर खासा जोर दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैसूर में पार्टी की जिला इकाई ने पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की शुरुआत करते हुए पार्टी के ढांचे में पूरी तरह से बदलाव किया है। मैसूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी जे विजयकुमार ने कन्नड़ मीडिया को बताया कि पार्टी ने विभिन्न इकाइयों के कामकाज का जायजा लिया और पाया कि कई के सक्रिय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे और कई वर्षों से निष्क्रिय थे।

खरगे ने पार्टी को दिए अपने नए साल के संदेश में कहा, 'यह वह साल साबित होना चाहिए जब हम हर भारतीय, विशेष रूप से सबसे कमजोर की आवाज उठाने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने संविधान और लोकतांत्रिक लोकाचार को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। हर भारतीय को यह महसूस करना चाहिए कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और उदार भारत के उनके सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने का माध्यम और साधन है।'क्या इसे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के पुनरुद्धार के आह्वान के रूप में देखा जाएगा? या यह कांग्रेस अध्यक्ष के मशहूर अंतिम शब्द बनकर न रह जाए? इस चुनौती पर पूर्ण सम्मेलन में बात की जाएगी।

गांधी आज

सत्याग्रही का अदालत में व्यवहार (भाग-02)

गतांक से आगे ...

जहाँ ऐसा जान पड़ता हो कि अधिकारियों ने उत्साह के अतिरेक में या भ्रम से ऐसे हुक्म निकाले हों जिनके बारे में यह मानने के लिए कारण। हो कि सरकार का इरादा वैसे हुक्म निकालने का नहीं था, और जिन कानूनों की रू से वे निकाले गए हों वे कानून वैसे अधिकार अधिकारियों को देते हैं यह न माना जा सकता हो तथा उन हुक्मों की बदौलत ऐसे साधारण लोगों के भी भारी संकट में पड़ने की संभावना हो जिनका इरादा सत्याग्रह करने का न हो, वहाँ सफाई पेश करने की आवश्यकता उपस्थित हो सकती है।

सत्याग्रही अदालत के काम में भाग न ले इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अदालत के प्रति तुच्छता या अविनय का व्यवहार करे, अथवा असत्याचरण करे। अत: उसे किसी अधिकारी का अपमान या उपहास न करना चाहिए और न उसे तुच्छतासूचक उत्तर देना चाहिए। इसके सिवा वह अपना नाम-धाम न छिपाए, परंतु यदि अधिकारी मामले से संबंध न रखनेवाली अथवा दूसरे अभियुक्तों या मनुष्यों से संबंध रखनेवाली बातें पूछें तो सत्याग्रही उनका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसे जवाब देने से उसे विनयपूर्वक इंकार कर देना चाहिए।

जबतक सत्याग्रही पुलिस की हिरासत में होता है तबतक उसे नहलाने-धुलाने, खिलाने-पिलाने तथा सलाहकार और मित्रों से मिलने की सुविधा देना और उसके प्रति सभ्यता का व्यवहार करना पुलिस का फर्ज़ है। उसी प्रकार सत्याग्रही का कर्त्तव्य है कि वह पुलिस के साथ शिष्टता का व्यवहार करे। अगर पुलिस की ओर से अड़चनें पैदा की जाएं, कष्ट दिया जाय, असभ्यता का बर्ताव या मारपीट की जाय तो सत्याग्रही को चाहिए कि वह इसकी सूचना पुलिस के बड़े अफसर को (वह मिल सके तो) दे, और वह न मिल सके या ध्यान न दे तो अपनी शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने रखे।

क्रमशः...

संक्षिप्त समाचार

राजस्व शिविर में 58 मामलों का निराकरण

बिलासपुर। राजस्व मामलों के निराकरण के लिए आज मस्तूरी तहसील कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 257 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 58 मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। आरबीसी के प्रावधानों के तहत 28 हितग्राहियों को 5 लाख 12 हजार रूपये की राशि के चेक वितरित किये गये। साथ ही 11 भू-स्वामियों को किसान-किताब तथा 100 से अधिक हितग्राहियों को जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये। ग्राम-आंकडीह के किसान शिवकुमार का नामांतरण तथा उनके रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही शिविर स्थल में ही किया गया।

भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड एवं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से विभिन्न प्रकार की दी जाती है अनुदान

रायपुर। भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड एवं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से विभिन्न प्रकार की अनुदान दी जाती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिको के लिये कल्याणकारी योजनाएं जैसे-पुत्री विवाह अनुदान- दो पुत्री को, पेनुअरी अनुदान-65 वर्ष से अधिक को, जंगी ईनाम-जिसका एक पुत्र या उससे अधिक संतान हो तथा वे सेना में कार्यरत हो या भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आता हो, चिकित्सा अनुदान-उनको दिया जाता है जो गंभीर बिमारी से पीडित हो। इसी तरह अन्य अनुदान भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष, मोती बाग रोड, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग) से कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2237449 और मो.नं. 7646853020 पर संपर्क कर सकते हैं।

उमंग-2023 के विजेताओं को मिले पुरस्कार

रायपुर। अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती में आज वार्षिक उत्सव उमंग-2023 सहित वर्ष भर में हुई गतिविधियों के विजेताओं को सम्मानित किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा रहे. वहीँ कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर नगर निगम के एम.आई.सी. सदस्य तथा पार्षद जितेन्द्र अग्रवाल ने की. इन दोनों अतिथियों के हाथों विजेताओं को ट्राफी, पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किये गए. मुख्य अतिथि श्री ज्ञानेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवावस्था में कड़ी मेहनत करने से बाद का जीवन सुरक्षित और सफल बनता है. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के साथ-साथ संस्कार शिक्षा, खेल-कूद और अन्य गतिविधियों को महत्व देने से विद्यार्थी का सम्पूर्ण विकास होता है. श्री शर्मा ने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामना दी. वर्ष भर अलग-अलग स्पर्धाओं में परिश्रम करने के बाद पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एम.आई.सी. सदस्य तथा पार्षद जितेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि इस महाविद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाता है. इसीलिए यहाँ के छात्र अनेक विधाओं में सफलता प्राप्त करते हैं, जो कि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का विषय है।

निरंजन दास को फिर से आबकारी विभाग का जिम्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी निरंजन दास को फिर से आबकारी विभाग में ले आई है। उनको आबकारी आयुक्त बनाया गया है। दास 31 जनवरी को इसी पद से रिटायर हुए थे। उसके तुरंत बाद एक फरवरी को उन्हें संविदा नियुक्ति देकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया था। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नियुक्ति का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक निरंजन दास को आबकारी आयुक्त, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक, स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी और वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।गौरतलब है कि एक फरवरी को उनको संविदा नियुक्ति दी जाते समय केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया था। 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होते समय दास के पास छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक, वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव, आबकारी आयुक्त और बेवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी की जिम्मेदारी थी। यह सभी विभाग अब फिर से दास के पास होंगे।

किसानों के साथ-साथ राईस मिलर्स हुए खुशहाल - बघेल

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की बेहतर नीति के फलस्वरूप किसानों के साथ-साथ राईस मिलर्स भी खुशहाल हैं। यही वजह है कि राज्य में हर साल जहां एक ओर कृषि रकबा, उत्पादन सहित कृषकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर राईस मिलों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य में राईस मिलों के संचालन के लिए माहौल उपयुक्त होने के कारण इस साल 249 नई राईस मिले स्थापित हुई हैं। इस तरह किसानों ही नहीं बल्कि राईस मिलरों में भी उत्साह का माहौल है और उनके लिए राईस मिल का संचालन एक लाभकारी व्यवसाय हो गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को राज्य में राईस मिलरों के हित में लिए गए निर्णय की वजह से स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य भर के सभी जिलों से आए राईस मिलर्स संघ के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कैलाश रूंगटा सहित पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में राज्य भर के राईस मिलर्स उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने एसोसिएशन को सम्बोधित करते हुए राज्य में हमारी सरकार न सिर्फ किसानों की उत्पादकता और आय में बढ़ोत्तरी के लिए काम कर रही है, बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हर उद्योग और उद्यम के विकास के लिए भी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए संकल्पित है। हमारी राईस मिलों का सीधा संबंध में हमारे खेतों से है। राइस मिलों की समस्याएं भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने राज्य में राईस मिलों से जुड़ी हर समस्या का निराकरण पूरी संवेदना और प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राईस मिलरों के हित को ध्यान रखते हुए हमने कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपए कर दी गई है। शासन के इस फैसले से राज्य के चावल उद्योग और राईस मिलर्स को नई ताकत मिल गई है। इसके फलस्वरूप राईस मिलर्स में उत्साह का माहौल है और उन्हें राईस मिल के संचालन में काफी सहुलियत हो गई है। इस साल राज्य में 249 नई राईस मिले स्थापित हुई हैं, जिसके कारण राज्य में कस्टम मिलिंग करने के लिए पंजीकृत मिलर्स की संख्या 2035 से बढ़कर अब 2284 हो गई है। इस तरह कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन की वजह से ही धान खरीदी और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

शासकीय जमीन पर अवैध कब्जाधारियों पर तहसीलदार की कार्यवाही, जारी किया नोटिस

■ ग्रामीण पटवारी पर लेनदेन कर कब्जा कराने के लग रहे आरोप

रायगढ़। घरघोड़ा के ग्राम पंचायत चोटिगुड़ा में अवैध बेजाकब्जा धारियों की आई बाढ़ सी आ गई है, शासन की बेशकीमती जमीन पर लोगो ने छोटे - बड़े झाड़ के जंगल खसरा न 10/1 रकबा 59.775 में अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर रहे है और पटवारी चैन की नींद सो रहा था । ग्रामीण की शिकायत पर तहसीलदार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बेजाकब्जा करने वाले 20 लोगो को नोटिस जारी किया गया है जिसमे ऋषिकेश पिता विरची दौलत पिता ऋषिकेश मंगल पिता कुलधर जगदीश पिता निरजन प्रहलाद पिता ऋषिकेश माधव पिता विरंची हरशंकर पिता परसू धोबनिन पति पद्मनाभो , डिलेश्वर पिता पालेश्वर रामकुमार पिता सहदेव जयानन्द पिता माधव जयजयराम पिता रवि मंगल पिता रवि संतोष पिता लबोराम बोधराम पिता दछू लवोराम पिता दछू पांडवो पिता जनकराम सदाशिव पिता लुकेश्वर घसियाराम पिता रामसिंह सभी निवासी चोटीगुड़ा तहसील घरघोड़ा को निर्माण कार्य पर रोक लगाये स्थगन आदेश जारी किया गया है।

बताना लाजमी होगा कि ग्राम पंचायत में इतने बड़े पैमाने में शासन के बहुमूल्य जमीन पर बेजाकब्जा धारियों के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करना हल्का पटवारी की मिलीभगत की बात सामने आ रहे है ।

निजी जमीन पर अतिक्रमण, सिक्ख समुदाय ने कलेक्टर और विधायक को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। सिक्ख समुदाय ने सड्डू में एक निजी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि स्व.जीतसिंग सग्गू द्वारा 7 मार्च 1984 को श्रीमती पाम बाई पिता रामलाल व 12 सितंबर 1984 को तुलसीराम से जमीन खरीदी थी। जिसके सभी रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। इस जमीन पर खेती किसानी की जा रही है। उक्त जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि इसकी सूचना 20 जनवरी 2023 को पहले भी प्रशासन को दी जा चुकी है। पांच लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत ज्ञापन में की गई है। इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक रायपुर को भी देते हुए तत्काल में प्रशासन से कार्यवाही की मांग समुदाय के सदस्यों ने की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पंडरी निवासी सग्गू परिवार के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सड्डू पटवारी हल्का न.109/44. तहसील व जिला रापुर मे स्थित भूमि, खसरा नंबर 7/38 रकबा 0.69 60 हे. एवं 7/57 रकबा 0.5060 है। खसरा नंबर 7138 सड्डू उरकुरा मेन रोड से लगी हुई है। ज्ञापन में समुदाय के लोगों ने यह भी बताया है कि तत्काल में अतिक्रमित जमीन से इन भू-माफियाओं को हटाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये,पूरी जमीन की रजिस्ट्री की वास्तविक दस्तावेज भी कलेक्टर को ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अलग-अलग गुरूद्वारा कमेटी से निरंजन सिंग खनूजा,सुरेन्द्र सिहं छाबडा,मंजीत सलूजा,इंदरजीत छाबडा,जसविंदर सिंह संधु, रखराज, लवलीअरोरा, दलजीत चावला,हरपाल भामरा सोनू सलूजा व अन्य शामिल थे।

पुलिस विभाग में 4 अधिकारियों के हुए तबादले

रायपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अफसरों को गृह विभाग के संयुक्त सचिव अभिजीत सिंह ने अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक ताबदला किया है। जिनमें डीआईजी पारुल माथुर भी शामिल है और उनकी जगह प्रखर पांडेय लेंगे जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा में पदस्थ थे। जारी आदेश के मुताबिक पारूल माथुर उप पुलिस महानिरीक्षक एसीबी मुख्यालय रायपुर से उप पुलिस महानिरीक्षक छसबल सरगुजा रेंज, प्रखर पाण्डे पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा रायपुर से उप पुलिस महानिरीक्षक एसीबी मुख्यालय रायपुर, राजेश कुकरेजा पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ से सेनानी, प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई तथा आशुतोष सिंह सेनानी 13 वीं वाहिनी छसबल कोरबा से पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ शामिल है।

दो माह में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने आरंग रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं सहित सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बंदोबस्त त्रुटि सुधार का कार्य दो माह के भीतर करने की निर्देश दिए। सभी विभाग के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 5-6 ग्राम पंचायतों का कलस्टर निर्धारित कर वहां शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

सचिव डॉ. भारतीदासन ने गौठानों में नियमित रूप से गोबर की खरीदी, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना तथा ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न आयमूलक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में पशुधन के लिए गौठानों में चारे-पानी का प्रबंध किए जाने के साथ ही पशुपालन के लिए ग्रामीण और किसानों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों का निर्माण, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, जल जीवन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सचिव डॉ. भारतीदासन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को जनोन्मुख बनाने तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों में लेट-लतीफी और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए। बैठक में स्पष्ट रूप हिदायत दी गई कि निर्माण कार्यो में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के उठाव और शत-प्रतिशत कस्टम मिलिंग कराये जाने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए प्रभावी पहल के भी निर्देश दिए गए।

ओपीएस या एनपीएस विकल्प समझने आज कार्यशाला

रायपुर। ओपीएस या एनपीएस पर वित्त विभाग के निर्देश के बाद प्रदेश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों को विकल्प चुनने कहा गया है। हालांकि विकल्प चयन को लेकर कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति भी बन गई है। पिछले सप्ताह कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पत्र जारी कर मांग की थी कि एक कार्यशाला का आयोजन कराया जाए, ताकि विकल्प चयन में आ रही भ्रम की स्थिति खत्म हो। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा की मांग पर इंद्रावती भवन के ट्रेजरी कार्यालय की तरफ से 9 फरवरी को एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

51 हजार से ज्यादा नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराए गए शासकीय दस्तावेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। योजना के तहत अब तक करीब 62 हजार लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर ही प्राप्त करने के लिए अपाइंटमेंट बुक करायें हैं। वहीं पर 51 हजार से अधिक नागरिकों ने घर बैठें ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 01 लाख 25 हजार से अधिक नागरिकों ने मितान योजना के टोल फ्री नम्बर 14545 पर सम्पर्क कर शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में व नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा 'मुख्यमंत्री मितान योजना' की शुरुआत 01 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी।

मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज, भूमि की रिकार्ड की नकल, भूमि सूचना (भूमि उपयोग), आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, पैन अपडेट एवं डूप्लीकेट इत्यादि सेवाएं घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है। साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से नागरिकों को घर बैठे ही शासकीय सेवायें की सुविधा मिल रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये आवेदक मितान की सेवा के लिये टोलफ्री नंबर 14545 पर कॉल करता है।

पंडो जनजाति बाहुल्य ग्राम के 47 घरों तक पहुंची पेयजल की सुविधा

रायपुर। जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से कोरिया जिले के पंडो जनजाति बाहुल्य ग्राम दुर्गापुर के सभी 47 घरों तक गुणवत्ता पेयजल की सुविधा पहुंच गयी है। स्वच्छ पेयजल की पहुंच से ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी है।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय से लगभग 18 किमी दूर विकासखण्ड बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत उमझर का आश्रित गांव दुर्गापुर, पंडो जनजाति बाहुल्य ग्राम है। वनवासी जीवन शैली के परिचायक दुर्गापुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को गुणवत्तायुक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। जहां चाह, वहां राह को आदर्श सूत्र मानते हुए दुर्गापुर के प्रत्येक परिवार को जल जीवन मिशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर कार्ययोजना बनाई गई और अंत में ग्रामवासियो के चेहरे की मुस्कान योजना के फलीभूत होने का प्रमाण खुद ही दे रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन अभियंता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में जल जीवन मिशन का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य समस्त ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना है। इस योजना के तहत मार्च, 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त ग्रामीण घरों में कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से उत्कृष्ट गुणवत्ता का पेयजल निरन्तर दीर्घ अवधि के लिए प्रदाय किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य में जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है।

पुरातात्विक धरोहरों को सहेज कर रखना सभी की जिम्मेदारी

इतिहासकार पुरातत्व नगरी सिरपुर में एक दिवसीय विचार संगोष्ठी का आयोजन

रायपुर। पुरातत्व नगरी सिरपुर में एक विचार विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी के दौरान रायपुर के वरिष्ठ इतिहासकार प्रो. डॉ. एस.एल. निगम, डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र और ग्राम सिरपुर निवासी प्रधान पाठक श्री आदित्य सिंह ठाकुर ने संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। इतिहासकारों ने संगोष्ठी में उपस्थित स्कूली बच्चों के सिरपुर और उससे जुड़ी इतिहास की जिज्ञासा और संबंधित प्रश्नों का समाधान भी किया। इस दौरान इतिहासकारों ने सिरपुर के वैभवशाली इतिहास के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस संगोष्ठी का आयोजन सिरपुर के कांवरिया शेड मेला मैदान में किया गया। संगोष्ठी में इतिहास में रुचि रखने वाले स्कूल, कॉलेज सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागी उपस्थित थे। संगोष्ठी के दौरान पुरातत्वविद डॉ.एल.एस. निगम ने कहा कि हम अपने पुरातात्विक चीजों को सहेज कर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने सिरपुर के ऐतिहासिक मन्दिर को बचा कर रखा है जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में दक्षिण कौशल में जो भी स्थापनाएं हुई वो आज पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सिरपुर के माटी-माटी में भगवान निवास करते है। आरंग और सिरपुर में ताम्र-पत्र मिले जिसे हमने शासन की मदद से सहेज कर रखा है। उन्होंने कहा कि जन जागरण में युवाओं की जिम्मेदारी है विकास के लिए कार्य करें ताकि हम अपनी संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों को बचा पाएं और इसके लिए हमें खुद जिम्मेदारी उठानी होगी। वक्ता श्री आदित्य सिंह ठाकुर ने विचार में बताया कि छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक धरोहर है।उनमें सिरपुर सबसे प्राचीन व विश्व प्रसिद्ध है। अभी भी इस शानदार जगह में कई अनछुए पहलू हैं। प्राचीन काल में यहाँ घने जंगल थे, महानदी के इस तट पर मिट्टी के बड़े-बड़े टीले थे। जिनके नीचे लक्ष्मण देव मंदिर, बोध प्रतिमाएँ आदि प्राचीन मूर्तियाँ मिली। संगोष्ठी के समापन के बाद अतिथियों और स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने सिरपुर के ऐतिहासिक स्थल का अवलोकन किया। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। आभार व्यक्त अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश कुमार वर्मा ने किया।

संक्षिप्त ख़बरें

भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने ली सहकारिता, पंचायत, नगरीय निकाय एवं विधि प्रकोष्ठ की बैठक

रायपुर। भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहकारिता प्रकोष्ठ, पंचायत प्रकोष्ठ, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ सहित मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के जिला संयोजकों की अलग-अलग बैठकें लीं। दिन भर चली बैठकों में भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन ने प्रकोष्ठों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए फीडबैक लिए एवं संगठनात्मक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा एवं ओपी चैधरी उपस्थित रहें। सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सहकारिता संबंधित खेती किसानी के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा चल रही गड़बडियों को जनता के बीच ला कर उजागर करने दिशा निर्देश दिये तथा सहकारी समितियों में नियम विरूध्द बैठे प्राधिकृत अधिकारियों की कारगुजारी जनता के सामने लाने को कहा व भंग समिति को गठित करने के लिए आंदोलन किए जाने की रणनीति बनाई गई। इसी तरह नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को निकायों में संपत्तिकर बढ़ोतरी आदि विषयों पर फोकस करने कहा गया । बैठक में मोर आवास-मोर अधिकार के सभी जिला संयोजक से उनके पंचायत स्तर तक डाटा मंगवा कर कार्य करने और वृहद रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान सभी प्रकोष्ठों को निर्देशित किया गया कि जरूरत पड़ने पर विधि प्रकोष्ठ से सलाह लेकर कानून सम्मत कार्यवाही करें एवं प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करे। इस मौके पर प्रमुख रूप से देवजीभाई पटेल, अशोक बजाज, पवन साहू, जेपी चंद्रवंशी, शशिकांत द्विवेदी, प्यारेलाल बेलचंदन, लाभचंद बाफना, अमित मैसेरी, जितेंद्र सुराणा सहित सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक मौजूद रहे।

स्वास्थ्य मंत्री आज कवर्धा प्रवास पर

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव 9 फरवरी को कवर्धा प्रवास पर जाएंगे। वे 9 फरवरी को शाम छह बजे रायपुर से सड़क मार्ग द्वारा कवर्धा के लिए रवाना होंगे। वे रात आठ बजे कवर्धा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि नौ बजे वहां से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री सिंहदेव रात 11 बजे वापस रायपुर पहुंचेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाया मुख्यमंत्री को आइना

यूपीए ने दी मुट्ठी भर और मोदी सरकार किसानों को दे रही थैला भरकर रकम- अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन मूल्य को लेकर किये गए दावे पर 2009 से लेकर 2014 तक हुई खरीदी के भुगतान और भाजपा शासन काल में 2014 से अब तक हुए भुगतान के आंकड़े पेश करने की चुनौती पर खामोशी ओढ़ लेने पर मुख्यमंत्री पर आंकड़ों के आधार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छल करने के लिए माफी मांगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस डर गई है। सच को छुपा रही है। इसलिए अब हम वह आंकड़े जारी कर रहे हैं। यूपीए शासन में 2009 से 2014 तक एमएसपी की कुल खरीद पर केवल 4.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ जबकि मोदी सरकार में 2014 से 2022 तक 14.25 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। धान खरीदी पर यूपीए शासन में 09 से 14 तक केवल लगभग 3 लाख करोड़ का भुगतान हुआ जबकि मोदी सरकार में लगभग 9 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। एमएसपी पर खरीद का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 में 1.71 करोड़, 2019 में 2.04 करोड़, 2020 में 2.10 करोड़।

उन्होंने कहा कि एमएसपी का सच तो यह है कि मोदी सरकार एमएसपी पर खरीदी के नए-नए रिकॉर्ड बना रही है और अधिक से अधिक किसानों को एमएसपी से लाभान्वित करने का भी रिकॉर्ड बना है। एमएसपी के रूप में किसानों को इतना पैसा दिया है कि पहले कभी किसी भी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। हर साल एमएसपी का दायरा बढ़ रहा है। इसका लाभ लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। धान, गेहूं, तिलहन और दलहन की खरीद में हर साल भारी वृद्धि हो रही है।

कृषि विकास और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में कृषि और किसान को सबसे ऊपर रखा है। इसीलिए पहली बार किसानों को खेती के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में मदद दी जा रही है।

- किसानों को पहली बार पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है।
- देश में लगभग 10 करोड़ छोटे किसानों की समस्याओं और उनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने बीज, बीमा, बाजार और बचत पर चहुंओर काम किया है।
- सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज का वितरण किया।
- किसानों को नीम का कोट किया हुआ यूरिया दिया। अब तरल नैनो यूरिया की फैक्टरी लगायी जा रही है।
- फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ज्यादा किसानों को इसके दायरे में लाया गया।
- आपदा के समय किसानों को अधिक मुआवजा दिलाने के लिए पुराने नियम बदले गए।
- पिछले चार वर्षों में किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा मिला है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत लगभग 11.74 करोड़ किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में लगभग 2.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिससे उनकी खेती-किसानी की जरूरतें पूरी हो सकें।
- किसानों को 22 करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इस अभियान से कृषि उत्?पादन भी बढ़ा है।
- मोदी सरकार का कृषि बजट पांच गुना बढ़ गया है। हर वर्ष कृषि पर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।
- 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा फंड (एग्रीकल?चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) है, जिसके माध्?यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं।
- छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने किसान उत्पादन संगठन बनाने आदि पर 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
- माइक्रो इरिगेशन फंड में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गयी, जो पहले से दोगुना है।
- मोदी सरकार ने 2023 के दौरान किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। 20 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। अब पशुपालन और मछलीपालन से जुड़े किसानों को भी क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है।
- अब तक 1.70 करोड़ से अधिक किसान और 1.63 लाख व्यापारी ई-नाम प?लेटफार्म पर पंजीकृत हुए हैं।
- सरकार ने अब तक देश की 585 मंडियों को ई-नाम के तहत जोड़ा है।
- सरकार की योजना इस साल 200 एवं अगले साल 215 और मंडियों को इससे जोड़ने की है।देश भर में करीब 2,700 कृषि उपज मंडियां और 4,000 उप-बाजार हैं।

धर्मांतरण के विरोध में दिया धरना

■ बेगुनाह आदिवासियों को रिहा करने कोंडागांव में किया प्रदर्शन

बलरामपुर। बलरामपुर जिला मुख्यालय में सर्व हिंदू समाज के द्वारा बस्तर नारायणपुर में हुए धर्मांतरण के विरोध एवं पूरे प्रदेश में जनजाति समाज का कराया जा रहे धर्मांतरण एवं अत्याचार किये जाने का आरोप लगाते हुए धरना सत्याग्रह पानी टंकी के समीप किया गया। धरना सत्याग्रह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जयसवाल, जनजाति गौरव समाज के प्रदेश महामंत्री राम लखन सिंह पैकरा, जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला संयोजक मेंहिलाल आयाम सहित बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस दौरान धर्मांतरण बंद किए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने नारायणपुर में 2 जनवरी को जनजाति समाज पर हुई हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा की कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्य जनक घटना था उपासने ने कहा कि बस्तर के अधिकारियों के द्वारा धर्मांतरण को लेकर राज्य शासन को आगाह किया गया परंतु राज्य शासन के द्वारा उसे गंभीरता से नहीं लिया गया जिस कारण से वहां धर्मांतरण लगातार हो रहा है एवं जो घटनाएं हुई वह इसी की परिणति थी। नारायणपुर में हिंसा करने वालों दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जनजाति गौरव समाज के प्रदेश महामंत्री राम लखन सिंह पैकरा ने कहा कि आदिवासी समाज के धर्म संस्कृति रीति रिवाज पर हमला किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं होगा उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक शक्ति की उपासना होती है। भक्ति की शक्ति है कि 9 दिनों तक कई लोग बिना जल के भी 9 दिन उपवास रह जाते हैं। सनातन संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा धर्मांतरण पूर्णता बंद होना चाहिए। सभा को भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शकुंतला सिंह पोर्ते, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा, जनजाति सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष महिलालायम आयाम, सुखनंदन किसान शिव शंकर सिंह मरावी संबोधित करते हुए सभी ने एक स्वर में कहां की हिंदू समाज पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा धर्मांतरण पूर्णता बंद हो।

ईधर, कोंडागांव में भी नारायणपुर में हुए घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। जनजातीय समूह के लोगों को जबरदस्ती अवैध धारा लगाकर जेल भेजा गया, जिसके विरोध में आज जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जेल भेजे गए जनजाति समूह के लोगो के रिहाई को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सभी वक्ताओं ने धर्मांतरण रोकने के लिए शासन प्रशासन से अपील किया गया और जेल में फंसे बेगुनाह आदिवासीयों को जल्द से जल्द रिहा करने की अपील किया गया। इस धरना कार्यक्रम मे पूर्व मंत्री लता उसेंडी, सेवकराम नेताम, दीपेश अरोड़ा, संगीता पोयाम, लक्ष्मी ध्रुव, अनीता नेताम, जसकेतु उसेंडी, करण उइके, कांतिभाई पटेल, हर्ष लाहोटी, संजू पोयाम दीपेंद्र नाग, विनय राज, संजू गहलोद व समस्त समाज के लोग मौजूद रहें।

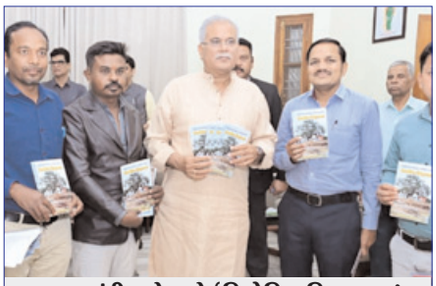

मुख्यमंत्री बघेल ने 'तिरोहित तितुरघाट' पुस्तक का किया विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में 'तिरोहित तितुरघाट' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक धमधा के तितुरघाट में दो दर्जन से अधिक सती स्तंभों के पुरातात्विक साक्ष्य और उनकी विशेषता पर आधारित है। इसका संपादन श्री गोविन्द पटेल ने किया है तथा भूमिका पुरातत्विद् प्रभात सिंह ने लिखी है। धर्मधाम गौरवगाथा समिति ने तितुरघाट के तिरोहित (भुला दिये गए) तालाब को फिर से ढूंढा और श्रमदान व जनसहयोग से उसकी फिर से खुदाई की। इस स्थान की प्राचीनता व ऐतिहासिकता के साथ ही तालाब के महत्व को दर्शाने इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मुख्यमंत्री भूपेश और कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम में चल रहा घमासान-नारायण चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने की बात आती है तो छत्तीसगढ़िया वाद की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कोई योग्य छत्तीसगढ़िया नहीं मिलता। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ को नियुक्ति पत्र लेने आने लायक ना समझने वाले केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला, और रंजीता रंजन को राज्यसभा सदस्य बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा सांसद बाहरी और कुलपति लोकल चाहिए ,जनता यह राजनीति बखूबी समझती है। उन्होंने कहा वास्तव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच कांग्रेस में वर्चस्व की जंग चल रही है । उन्होंने कहा मोहन मरकाम जी ने कुलपति चयन के बहाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की संस्कृति के अनुसार श्रेय लेने की राजनीति के तहत आपसी लड़ाई अब बाहर आ गई है। लंबे समय तक सत्ता और संगठन के निशाने पर रहकर उपेक्षा झेल रहे मोहन मरकाम को कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा जी के आने से बल मिल गया लगता है।

चालू वित्तीय वर्ष में छठवीं बार रेपो रेट बढ़ाकर मोदी सरकार ने दिया झटका

रायपुर। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। विगत 9 महीनों के भीतर छठवीं बार रेपो रेट बढ़ाना यह प्रमाणित करता है कि मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और आज् पुन: रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। विदित हो कि इसी वर्ष 4 मई को 0.40 प्रतिशत, 8 जून को 0.50 प्रतिशत, 5 अगस्त को 0.50 प्रतिशत, 30 सितंबर को 0.50 प्रतिशत 7 दिसंबर को 0.35 प्रतिशत और अब आज् 8 फरवरी को 0.25 अर्थात चालू वित्त वर्ष के विगत 9 महीनों में ही कुल 2.50 प्रतिशत बढाया गया है। रेपो रेट फिर से बढ़ाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ना निश्चित है। इससे पहले आरबीआई पांच बार की मॉनिटरी पॉलिसी बैठकों में पहले ही 2.25 फीसदी रेपो रेट को बढ़ा चुकी है। अनुमान है कि 20 साल की अवधि के लिए 30 लाख के लोन पर ढाई परसेंट बढ़ोतरी पर प्रत्येक माह लगभग 4657 का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी और आय में कमी की मार झेल रहे आम जनता पर यह एक और अत्याचार है।

पूर्ववर्ती रमन सरकार नक्सलवाद की पोषक थी-कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती रमन सरकार नक्सलवाद की पोषक थी। नक्सलवाद यानी हिंसा और हिंसा की सोच और समर्थक भाजपा भी है। भाजपा अपनी विचारधारा को मनाने के जनमानस को डराते धमकाते है और हिंसा करने पर भी उतारु रहती है जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां हिंसक घटनाएं होना आम बात है। प्रदेश में नक्सलवाद पनपने के पीछे भी पूर्व रमन भाजपा सरकार की नाकामी ही रही है भाजपा की घिनौनी राजनीतिक स्वार्थ और बस्तर की जल, जंगल, जमीन का दोहन करने की बदनीयती के ही चलते प्रदेश के 4 विकासखण्ड तक सीमित नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंचा था। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार विश्वास विकास और सुरक्षा के नीति के तहत प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने काम कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नया अध्याय लिखा गया है, बंद स्कूलों को खोला गया, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की गई, स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया गया, आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार दिया गया, जेल में निर्दोष बंद आदिवासियों को रिहा किया गया, इसका ही परिणाम है कि प्रदेश में नक्सली घटनाओं में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है।

9 साल से प्रधानमंत्री सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और अपनी नाकामी छुपा रहे हैं-कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के द्वारा सदन में जो सवाल उठाए गए उन सवालों के जवाब देने से मोदी सरकार बचती रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा सदन में दी गई एक घंटा तेरह मिनट के भाषण में सिर्फ झूठ की ख्याली पकवान ज्यादा थी। मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बताने में पूरी तरह नाकाम रही है और मोदी के परम मित्र के फॉड पर देश की जनता का ध्यान हटाने बेतुकी बातें कही गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमेशा की तरह आज एक बार फिर मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च सदन से देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। हिडनबर्ग खुलासे के बाद अडानी के घपलेबाजी पर प्रधानमंत्री की राय देश की जनता जानना चाहती थी। जेपीसी की जांच की घोषणा की उम्मीद थी लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया अडानी को खुश। आम जनता की मूलभूत समस्याओं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ` पर जनता जवाब चाह रही थी। अडानी के हेराफेरी उजागर होने के बाद जनता को बैंक एवं एलआईसी में फंसी अपनी गाढ़ी कमाई डूबने की चिंता सता रही है उसका जवाब चाह रही थी।

भूपेश सरकार की नीति के कारण धान के किसान, रकबा, पैदावार, दुगुना हो गया - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह भूपेश सरकार की खेती किसानी को बढ़ावा देने नीति का परिणाम है कि वही प्रदेश है वही भू-भाग है लेकिन 4 साल में भाजपा राज की तुलना में दुगुने किसान लगभग 24 लाख धान बेचे, दुगुनी धान 107.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, दुगुने रकबे 30 लाख हेक्टेयर पर धान की पैदावार हुई है। धान खरीदी में भाजपा की केन्द्र सरकार के सिवाय अडंगेबाजी के कुछ नहीं किया है। भाजपा आदतन किसान विरोधी है। चुनाव में मत लेने के लिये वह किसानों के हितों की बात करती है। चुनावी घोषणा पत्र में वायदा करती है। सरकार में आने के बाद वह भूल जाती है। मोदी सरकार किसानों को धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा मिलने में रोक लगाती है। मोदी सरकार की अडंगे बाजी के कारण कांग्रेस सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रू. एक मुश्त नहीं मिल पाता। मोदी सरकार की किसान विरोधी चरित्र के कारण कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों को प्रति एकड़ 9000 रू. इनपुट सब्सिडी देना किया जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2640 रू. से अधिक मिला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी का अंतर हमेशा अलग रही।

रेल टिकट दलालों की आयी शामत,कार्रवाई में कई पकड़ाए

रायपुर। रायपुर रेल मंडल में इन दिनों टिकट दलालों के खिलाफ छापा मार कार्रवाई चल रही है। 2 दिनों में अब तक 8 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों के पास से करीब 5 लाख 12 हजार रूपए की टिकटें जब्त की गई है.दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के आईजी अमिय नंदन सिन्हा और रायपुर रेल मंडल के कमांडेंट संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। रे. सु. ब.. सेटलमेंट पोस्ट के द्वारा सड्ड, विधानसभा लावन्या स्टोर डेयरी एंड जनरल स्टोर में कार्रवाई की गई. यहां से चेतन कुमार उम्र 39 वर्ष, निवासी- गैलेक्सी आइलैंड, विधानसभा रोड, महालेखाकार के पास, संकरी, रायपुर (छ. ग.) के कब्जे से पर्सनल यूजर आईडी से 15 ओल्ड रेल आरक्षित ई टिकट प्राप्त हुई. जब्त टिकटों की कीमत करीब 8500 रूपए है। सीआईबी भिलाई ने नंदनी रोड के अरूण ट्रेवल्स में छापा मारा। यहां से आरोपी सचिन कुमार पाटिल को हिरासत में लेकर 85 हजार रूपए की 69 टिकटें जब्त किया है। मां लक्ष्मी कंप्यूटर (देवकर) में छापा मारा। यहां से लव कुश साहू को हिरासत में लिया आरोपी के पास से 9 टिकटें जब्त हुई है, जिसमें से 5 आगामी यात्रा की टिकटे है। जब्त टिकटों की कुल कीमत करीब 16 हजार रूपए बताई जा रही है। वहीं धमतरी के थाना भखारा स्थित श्रीकृष्णा च्वाईस सेंटर में छापा मारा। यहां से 33 टिकटें करीब 33 हजार रूपए की जब्त की गई. आरपीएफ की टीम ने यहां से रेखराम सिन्हा को गिरफ्तार किया। एक और कार्रवाई में रायपुर आरपीएफ पोस्ट की टीम ने धमतरी के ही वीकेंड हॉलीडे शॉप कुरूद में छापा मारा. यहां से आरपीएफ की टीम ने 52 टिकटें जब्त की, जिसकी कुल कीमत करीब 1.50 लाख रूपए आंकी गई है।

मुख्यमंत्री रायपुर आर्च डायसिस के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल

शिक्षा, स्वास्थ और मानवता की सेवा के कार्य सराहनीय- मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के अम्लीडीह स्थित कैथोलिक चर्च में रायपुर आर्च डायसिस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ईसाई समाज द्वारा किए गए शिक्षा, स्वास्थ और मानवता सेवा के कार्य सराहनीय हैं, उनका कोई सानी नहीं है। जब शिक्षण संस्थाओं का अभाव था, तब मसीही समुदाय ने स्कूल और हॉस्टल खोले। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया। ईसाई समाज ने शिक्षा और स्वस्थ्य के क्षेत्र में सेवा के कार्यों को ऐसे स्थानों तक भी पहुंचाया जहां लोगों का पहुंचना भी कठिन था।

श्री बघेल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी ईसाई समुदाय तत्परता के साथ मानवता की सेवा की। जब कुष्ठ रोग पीड़ितों को लोग छूने से भी संकोच करते थे तब इस समाज ने कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया। कुष्ठ रोग पीड़ितों के इलाज के लिए ईसाई समाज ने अभनपुर, बैतलपुर समेत कई स्थानों पर हॉस्पिटल व डिस्पेंसरी खोले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईसाई समुदाय का छत्तीसगढ़ से पुराना नाता रहा है। यह समुदाय प्रभु यीशु और संत माता मरियम की दया, करुणा, सेवा, क्षमा, प्रेम, त्याग की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित भारत और नेपाल के लिए वेटिकन के राजदूत श्री लियोपोलोदो जिरेल्ली सहित स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित कार्डिनल, आर्च, बिशप, गण फादर, सिस्टर्स और समाज के लोगों का छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत करते हुए उपस्थित सभी लोगों को स्वर्ण जयंती समारोह की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके पहले वेटिकन के राजदूत लियोपोलोदो जिरेल्ली और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। वेटिकन के राजदूत लियोपोलोदो जिरेल्ली ने रायपुर आर्च डायसिस के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पोप फ्रांसिस और अपनी ओर से सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

उन्होंने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध और गौरवशाली संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोक संगीत, लोक कला और छत्तीसगढ़ की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चन एजुकेशनल सोसायटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और ईसाई समुदाय द्वारा स्वास्थ और सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि रायपुर आर्च डायसिस की स्थापना 5 जुलाई 1973 को की गई थी।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.